झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक रिट याचिका संख्या 1229/2023

गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची के माध्यम से झारखंड राज्य प्रभात कुमार, उम्र लगभग 47 वर्ष,पिता स्वर्गीय डॉ. जे.एस. सिन्हा, महानिरीक्षक, प्रावधान, पुलिस मुख्यालय, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, रांची। **.....याचिकाकर्ता**

बनाम

1. केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिनिधित्व, इसके निदेशक, प्लॉट नंबर 5-बी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, डाकघर और थाना लोधी रोड, नई दिल्ली में कार्यालय से कार्य कर रहे हैं।
2. बिजय हांसदा उम्र लगभग 51 वर्ष पिता दशमत हांसदा निवासी भवानी चौकी, अंबाडीहा, मंडरो, डाकघरऔर थाना मिर्जा चौकी, जिला साहिबगंज।

... ... उत्तरदाता

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत-नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए: श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री राजीव रंजन, महाधिवक्ता सुश्री प्रज्ञा सिंह, अधिवक्ता
सुश्री अपराजिता जामवाल, अधिवक्ता
श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता
श्री पीयूष चित्रेश, ए.जी. के एसी

सीबीआई के लिए : श्री अनिल कुमार,ए.एस.जी.1
सुश्री चंदना कुमारी, एडवोकेट

16.02.2024 को सीएवी **23/02/2024 को सुनाया गया**

प्रति सुजीत नारायण प्रसाद, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड राज्य द्वारा गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची के माध्यम से दायर की गई तात्कालिक रिट याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो के खिलाफ निर्देश की मांग की गई है।

2. तत्काल रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं: -

"(i) प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट या कोई अन्य उपयुक्त आदेश, रिट निर्देश जारी करना जो सीबीआई, एसीबी, रांची दिनांक 20.11.2023 के आरसी वाद संख्या 0242023S0011 है, जो डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665/2022 में पारित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 18.08.2023 के आदेश के आधार पर दर्ज किया गया है, सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी दिल्ली की धारा 6 का स्पष्ट उल्लंघन है (ख) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 का स्पष्ट उलंघन है क्यों कि प्राथमिकी दर्ज करने और उत्तरदाताओ द्वारा मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार से कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई है।

(२) घोषणा रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, कि उत्तरदाता की शक्ति जहां तक यह संबंधित राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर और भीतर उत्पन्न होने वाले किसी भी अपराध की जांच आदि से संबंधित है, संबंधित राज्य की सहमति के बिना प्रतिबन्धित है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के तहत सीधे धारा 6 के उल्लंघन में और संघवाद की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है और शक्तियों के पृथक्करण पर रोक लगा दी गई है, और इसलिए प्रतिवादी द्वारा ऐसी अनुसंधान, जांच आदि केवल राज्य एजेंसियों/राज्य सरकार के अनुरोध पर या माननीय संवैधानिक न्यायालय के निर्देशों के तहत की जा सकती है।

(३) रिट याचिका (सीआर) संख्या 665/2022 में पारित दिनांक 18.08.2023 को सीबीआई, एसीबी, रांची के एफ आर आर वाद संख्या 0242023S0011 के संबंध में आगे की अनुसंधान पर अंतरिम रोक का आदेश जारी करें।

(४) इस तरह के अन्य और आगे के आदेश या राहत को

पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझ सकता है।

3. दलील के आधार पर रिट याचिका में की गई प्रार्थना कानूनी मुद्दों का जवाब देने के लिए है कि क्या एक बार अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने और इसके निष्कर्ष के बाद या इस उद्देश्य के लिए नियमित मामले के मध्य में पंजीकरण करने का निर्देश दिया है

उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें नया वकालतनामा प्राप्त हुआ है और वह रिट याचिका वापस लेने के लिए आईए दायर करना चाहते हैं और 17.08.2023 को दोपहर 2.15 बजे मामले की सुनवाई की प्रार्थना की गई एवं जब मामला की सुनवाई होने लगी तो श्री जेपी झा वरिष्ट अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए और प्रस्तुत किये कि रिट याचिका को वापस लेने के लिए वादकालीन आवेदन तैयार किया गया है लेकिन इसे दायर नहीं किया जा सका। तथापि, इसकी प्रति प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील के साथ-साथ राज्य को भी दी गई थी।

4. 17.08.2023 को न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया कि उत्तरदाता नंबर 2 (डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665/2022 याचिकाकर्ता) जेल हिरासत में था और उसे रिट याचिका दायर करने की जानकारी नहीं थी और उसके विरोधी किसी व्यक्ति ने रिट याचिका दायर की है और तदनुसार रिट याचिका वापस लेने की प्रार्थना की है।

5. पक्षों के प्रतिद्वंद्वी कथन(दलिल) और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में तथ्यों के विवादित प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, माननीय न्यायालय ने आईए संख्या 7438/2023 में की गई प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए उपयुक्त पाया और वापसी के लिए प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और तदनुसार उक्त अंतरवर्ती आवेदन में की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।

6. मुख्य मामले पर 18.08.2023 को भी सुनवाई की गई, जिसमें पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि "*यदि निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस याचिकाकर्ता सहित पहल करने का निर्देश दिया*

जाता है तो यह पर्याप्त रूप से दिया *जाएगा*

7. सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता - राज्य ने सीबीआई, एसीबी, रांची के दिनांक 20.11.2023 के आरसी वाद संख्या 0242023S0011 होने के नाते प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

8. उक्त बिजय हांसदा ने आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 323, 500, 504, 506, 120बी और 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 27, जेएमएमसी के नियम 04/54 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (एस) के तहत दर्ज एससी/एसटी साहिबगंज वाद संख्या 06/2022 दिनांक 01.12.2022 के तहत अनुसंधान सीबीआई को सौंपने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी और इसके साथ-साथ प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने के लिए और उचित आदेश के लिए आगे प्रार्थना की गई जैसा कि यह न्यायालय उचित समझ सकता है।

9. जब रिट याचिका लंबित थी, तो एक अंतरवर्ती आवेदन आई.ए. संख्या 7438/2023 बिजय हांसदा द्वारा डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665/2022 होने वाली रिट याचिका को वापस लेने के लिए दायर की गई थी।

10. समन्वय विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 17.08.2023 के आदेश के तहत मामले के पूरे मामलों पर ध्यान दिया है और साथ ही एक अन्य वकील, श्री एसएस चौधरी द्वारा दायर किया गया आवेदन भी, यहां तक कि उक्त बिजय हांसदा द्वारा निष्पादित वकालतनामा की उपस्थिति

में भी जेल प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था, रिकॉर्ड में था।

11. समन्वय पीठ ने पूर्वोक्त तथ्य के बारे में चिंता व्यक्त की है और प्रथम दृष्टया विचार पर आया है कि इस तरह की वापसी याचिका उक्त बिजय हांसदा के इशारे पर दायर की गई है जो पर्दे के पीछे है।

12. उपरोक्त पृष्ठभूमि में उपरोक्त वादकालीन आवेदन को दिनांक 17.08.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, तैयार संदर्भ के लिए उक्त आदेश को इस प्रकार संदर्भित किया जा रहा है: -

> "**05/17.08.2023** यह मामला कल सीरियल नंबर 53 पर सूचीबद्ध किया गया था और श्री आशीष कुमार ठाकुर, विद्वान ए.सी.
> एसएस चौधरी, विद्वान वकील ने इस मामले का उल्लेख इस आधार पर किया कि वह केवल इस रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, उसी के मद्देनजर, उनकी प्रार्थना को अनुमति दी गई थी कि इस मामले को आज पूरक सूची में सूचीबद्ध किया गया था।
>
> 2. आज, जब यह मामला लिया गया था, श्री एसएस चौधरी ने कहा था कि यह विधेयक उठाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील चौधरी ने प्रस्तुत किया कि उन्हें नया वकालतनामा प्राप्त हुआ है और वह रिट याचिका को वापस लेने के लिए आईए दायर करना चाहते हैं और प्रार्थना की गई थी कि इस मामले को दोपहर 2.15 बजे लिया जाए। इस प्रकार के निवेदन को देखते हुए, मामले को पारित कर दिया गया था और इसे मध्याह्न पश्चात् 215 बजे पुन लिया गया था। जब मामला उठाया गया, तो याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जेपी झा उपस्थित हुए और उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2023 का आईए नंबर 7438 वर्तमान रिट याचिका को

वापस लेने के लिए तैयार किया गया है। तथापि, इसे रजिस्ट्री में दायर नहीं किया गया था क्योंकि मामला बोर्ड के पास था। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त आईए की प्रति पहले ही प्रवर्तन निदेशालय के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वकील के साथ-साथ राज्य के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वकील को दी जा चुकी है। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त आईए को कृपया अभिलेख पर लिया जाए।

3. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील की इस तरह की दलील के मद्देनजर, उक्त आई.ए. को अभिलेख पर लिया जाय

4. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जेपी झा ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता जेल की हिरासत में है और

क्योंकि उसने एनओसी प्राप्त करके एक नए वकील द्वारा दायर वकालतनामा पर रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है और इसके मद्देनजर रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से जांच के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना भी उचित होगी। इस प्रकार, प्रारंभिक जांच कानून के अनुसार की जाएगी और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो जाएगी।

1. न्यायालय द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने और इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद निदेशक, सीबीआई कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2. न्यायालय के निर्देश के अनुसार सीबीआई को उत्तरदाता संख्या 2 के संबंध में प्रारंभिक जांच करनी थी, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 (डब्ल्यूपी

(सीआर) संख्या 665/2022 में याचिकाकर्ता) और उक्त घटना में शामिल आरोपी व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाया गया था और उसके बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जानी थी।

3. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि सीबीआई ने 2022 की डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665/2023 के आईए संख्या 7438 होने के कारण अंतरवर्ती आवेदन में नामित आरोपी व्यक्तियों के आचरण के संबंध में जांच करने के माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया और उच्च न्यायालय परिसर में प्रतिवादी नंबर 2 को धमकी देने की घटना और इसके विपरीत, एसटी/एससी के एफ आई आर

में लगाए गए आरोपों के संबंध में जाँच किया गया है और इसके अनुसार सहमति प्राप्त किए बिना, जैसा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत आवश्यक है, प्राथमिकी दर्ज की गई है जो पूरी तरह से कानून के जनादेश के खिलाफ है और इसलिए अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में सीबीआई की कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप नहीं है और, इस तरह, यह अवैध, दुर्भावनापूर्ण है और डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665/2022 में पारित माननीय न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल है।

4. प्रारंभिक जांच करने के बाद, सीबीआई ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 2023 की सीआरएमपी संख्या 3378 के तहत 2022 की डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2023 में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया, इस हद तक कि प्रारंभिक जांच के बाद के घटनाक्रम को देखते हुए प्राथमिकी संख्या 6/22 एसटी/एससी पीएस साहिबगंज दिनांक 01.12.2022 की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए।

5. सीबीआई द्वारा दायर उक्त आवेदन में, सीबीआई ने जांच के उद्देश्य से जिला पुलिस से प्राथमिकी संख्या 06/2022 की जांच अपने हाथ में लेने में आगे की कार्रवाई करने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 की कानूनी बाध्यता है जिसके लिए यह आवश्यक है कि सीबीआई द्वारा जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है और वर्तमान मामले में

प्राथमिकी संख्या 6/2022 का अनुसंधान अपने हाथ में लेने का राज्य सरकार की कोई सहमति नही है और उसके अभाव में उक्त मामले की जांच सीबीआई द्वारा नहीं ली जा सकती है।

6. सीबीआई द्वारा मामले को सौंपने के लिए आदेश में संशोधन के लिए दायर आवेदन को इस न्यायालय ने दिनांक 03.11.2023 के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया था और माननीय न्यायालय ने पहले के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और सीबीआई द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

7. याचिकाकर्ता का यह और मामला है कि 1946 के अधिनियम की धारा 6 के अनिवार्य प्रावधान का पालन किए बिना, सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, एससी/एसटी अधिनियम और झारखंड खान और खनिज रियायत नियम, 2004 की विभिन्न धाराओं के तहत दिनांक 20.11.2023 को RC0242023S0011 प्राथमिकी दर्ज की, जो कथित तौर पर उच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवहेलना में 2022 की डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665 में दिनांक 18.08.2023 के आदेश के आधार पर और झारखंड राज्य से सहमति प्राप्त किए बिना।

8. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि अन्यथा भी पुलिस ने

एससी/एसटी 06/2022 में प्राथमिकी में अपना अनुसंधान पूरी कर ली है और दिनांक 26.10.2023 को अंतिम फॉर्म जमा कर दिया है और क्योंकि राज्य सरकार या संवैधानिक अदालतों से अनुमति प्राप्त किए बिना सीबीआई द्वारा आगे की अनुसंधान का कोई अवसर नहीं था।

9. इसके अलावा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की आड़ में,

इसके तहत कार्य करने वाले प्राधिकारी उन मामलों में कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है जिनमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तरह की कार्रवाई/शक्ति का प्रयोग कानून में दुर्भावना के कारण दूषित होगा और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका एफ.आई.आर. RC0242023S0011 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

10. तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि बिजय हांसदा नामक व्यक्ति ने अवैध खनन और उस पर हमले के संबंध में 30.06.2022 को आपराधिक परिवाद पत्र दर्ज कराकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, साहिबगंज से संपर्क किया।

11. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, साहिबगंज ने 07.07.2022 को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच करने का आदेश पारित किया।

12. उक्त बिजय हांसदा ने पुलिस अधीक्षक को दिनांक 27.9.2022 को एक पत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि वह शिकायत संख्या 44/2022 को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि शिकायत झूठी है और उन्होंने अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा द्वारा सत्यापित हलफनामा दायर किया है।

13. 12.11.2022 को बिजय हांसदा और उनके बेटे मनोज हांसदा को बोरियो पीएस जिरवाबारी ने शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज 2022 की प्राथमिकी संख्या 286 में गिरफ्तार किया था। वह 07.06.2023 तक न्यायिक हिरासत में रहे। बिजय हांसदा जेल में थे, लेकिन उन्होंने अपने वकील संजय कुमार जायसवाल के माध्यम से एससी/एसटी कोर्ट, साहिबगंज में एक आवेदन दायर किया कि वह परिवाद पत्र की सामग्री की पुष्टि करते हैं और आरोपी गुड्डू यादव ने बिजय हांसदा द्वारा हस्ताक्षरित कुछ कागजात प्राप्त किए हैं

और वह अपने मामले को विफल करने की कोशिश कर सकता है और उसकी परिवाद पत्र पुलिस को भेजी जा सकती है।

14. पुलिस ने बिजय हांसदा द्वारा दायर एससी/एसटी शिकायत संख्या 44/2022 के आधार पर एससी/एसटी साहिबगंज पीएस वाद संख्या 06/2022 दिनांक 01.12.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 323, 500, 504, 506, 120बी और 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 27, जे एम एम सी के नियम 04/54 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। नियम और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (एस)।

15. जब पुलिस विद्वान सीजेएम, साहिबगंज के निर्देशानुसार मामले की जांच कर रही थी, तो उक्त बिजय हांसदा ने आपराधिक रिट याचिका संख्या (सीआर) संख्या 665/2022 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें झारखंड राज्य को एससी/एसटी पीएस वाद संख्या 06/22 दिनांक 01.12.2022 की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई।

16. राज्य ने अब तक की गई जांच का ब्यौरा देते हुए जवाब दायर किया।

17. प्रवर्तन निदेशालय ने भी जवाब दाखिल करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने प्राथमिकी संख्या 06/2022 के आधार पर पहले ही ईसीआईआर/आरएनजेडओ/07/2023 दर्ज कर लिया है।

18. इसके बाद, 2022 की रिट याचिका डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665 को उच्च न्यायालय द्वारा 16.08.2023 को लिया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अदालत को सूचित किया कि बिजय हांसदा मुख्य याचिका वापस लेना चाहते हैं।

इसके बाद, मामले पर विचार करने के लिए 17.08.2023 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

19. 17.08.2023 को, एक अन्तरवर्ती आवेदन किया जा रहा है आईए संख्या 7438/2023 दायर किया गया था जिसमें रिट याचिका को वापस लेने की मांग की गई थी क्योंकि वकालतनामा दिनांक 08.12.2022 को जमानत आवेदन दायर करने की आड़ में लिया गया था।

20. विद्वान समन्वय पीठ ने तर्क सुनने के बाद, रिट याचिका को वापस लेने के लिए अंतरवर्ती आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मामले को 18.08.2023 को पोस्ट कर दिया।

21. 18.08.2023 को, विद्वान समन्वय पीठ ने सीबीआई द्वारा व्यक्ति के साथ-साथ बिजय हांसदा के आचरण के बारे में प्रारंभिक जांच का आदेश देने का निर्देश दिया और रिट याचिका का निपटारा किया।

22. रिट याचिका में विद्वान समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2023 के खिलाफ, पंकज मिश्रा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें अपील की विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या 12087/2023 दिनांक 18.08.2023 के आदेश के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने के लिए जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

23. पुलिस ने प्राथमिकी में उल्लिखित सभी 8 आरोपियों के खिलाफ 26.10.2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, साहिबगंज की अदालत में अंतिम फॉर्म प्रस्तुत किया।

24. 20.11.2023 को सीबीआई ने भारतीय दण्ड संहिता, शस्त्र अधिनियम अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अधिनियम और झारखंड

खान और खनिज रियायत नियम, 2004 की विभिन्न धाराओं के तहत RC0242023S0011 प्राथमिकी दर्ज की।

धारा 173 सीआरपीसी के प्रावधान के आलोक में अनुसंधान प्राप्त करने में शामिल है, इसलिए, उक्त बिजय हांसदा को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह न्यायालय तथ्यात्मक पहलू में नहीं जा रहा है जैसा कि रिट याचिका में या झारखंड राज्य की ओर से दायर पूरक हलफनामे में की गई दलील के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है।

25. वह तथ्य जिसने रिट याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए प्रेरित किया, पूर्वोक्त निर्देशों की मांग करते हुए, निम्नानुसार है: -

सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तरदाता नं. 2 खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए आरोपी बिष्णु प्रसाद यादव, पवित्र कुमार यादव, राजेश यादव, संजय यादव, बच्चा यादव, सुधेश मंडल और पंकज मिश्रा के साहिबगंज, झारखंड में बड़े पैमाने पर चल रहे खनन घोटाले में शामिल होने के बारे में पता चला और आगे आरोप लगाया कि उपरोक्त आरोपी श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखण्ड के करीबी सहयोगी हैं। और राज्य के अधिकारियों और उच्चाधिकारियों की मिली भगत से साहिबगंज जिले में अवैध खनन में संलिप्त है

26. उत्तरदाता नंबर 2 ने आगे आरोप लगाया कि 02.05.2022 को जब उसने आरोपी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, तो भारी हंगामा हुआ, जिसके कारण लगभग 50 स्थानीय ग्रामीण

"निम्बू पहाड़" में जमा हो गया और इस दौरान आरोपियों ने अपने अंगरक्षकों को जो राइफल लिए थे, ग्रामीणों को , को मारने के लिए कहा और नंबर 2 को धमकी देना शुरू कर दिया।

27. प्रतिवादी नंबर 2 ने एसटी/एससी पुलिस स्टेशन, साहिबगंज में प्राथमिकी के रूप में उक्त घटना दर्ज करने की कोशिश की, हालांकि, इससे इनकार कर दिया गया और उसके बाद, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए ऑनलाइन परिवाद पत्र दर्ज की।

28. इसके बाद, उत्तरदाता नंबर 2 ने आपराधिक शिकायत परिवादपत्र दर्ज करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, साहिबगंज से संपर्क किया, जिसके अनुसार विद्वान न्यायालय ने 7 जुलाई, 2022 के आदेश के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए धारा 156 (3) के तहत एक आदेश पारित किया, लेकिन इसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और उसके बाद आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एसटी/एससी पीएस केसनिचली नंबर 6/22 के तहत विद्वान निचली अदालत में शिकायत परिवादपत्र दर्ज की गई।

29. जब पुलिस विद्वान सीजेएम, साहिबगंज के निर्देश के अनुसार मामले की जांच कर रही थी, तो प्रतिवादी संख्या 2 ने डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665/2022 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें झारखंड राज्य को एसटी/एससी पीएस वाद संख्या 06/22 दिनांक 01.12.2022 को सीबीआई को मामले की जांच सौंपने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई।

30. जब मामला आपराधिक रिट आवेदन की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, तो उत्तरदाता नंबर 2 ने श्री एसएस चौधरी, एडवोकेट के माध्यम से आईए संख्या 7438/2023 होने के नाते एक वादकालीन आवेदन दायर किया।

और वे

रिट याचिका दायर करने के बारे में पता नहीं है और किसी ने जो उसके प्रति प्रतिकूल है, वर्तमान रिट याचिका दायर की है और इस पृष्ठभूमि पर, वह प्रस्तुत करता है कि उपरोक्त आईए में की गई प्रार्थना को कृपया अनुमति दी जाए और रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

5. अदालत ने उपरोक्त आईए में लगाए गए आरोपों को देखते हुए, श्री अमित सिन्हा और श्री पार्थ जालान, विद्वान वकीलों, जो अदालत में मौजूद हैं, को भी सुना और वे संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें वकालतनामा प्राप्त हुआ, जिसे साहिबगंज जेल के जेलर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था और पैरबिकार ने उनसे संपर्क किया है और निर्देश के मद्देनजर उन्होंने रिट याचिका दायर की है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक समय, उनसे एनओसी मांगी गई थी, उन्होंने याचिकाकर्ता को एनओसी दे दी है।

6. श्री अनिल कुमार, प्रतिवादी नंबर 3 (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से पेश होने वाले विद्वान एएसजीआई ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने के लिए दायर उपरोक्त आईए में की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया। वह प्रस्तुत करता है कि रिट याचिका में, एससी/एसटी थाना कांड संख्या 06/2022 की उचित जांच के लिए प्रार्थना की गई है। याचिकाकर्ता को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया है। वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि इस याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जांच की है और जांच में, झारखंड राज्य के उच्चाधिकारियों के खिलाफ कई सामग्रियां आई हैं, जिनमें श्री पंकज मिश्रा, जो झारखंड राज्य

के मुख्यमंत्री से जुड़े हैं। वह आगे प्रस्तुत करता है कि रिट याचिका वापस लेने के माध्यम से पूरी प्रक्रिया, जांच को विफल करने के लिए स्थापित की गई है, जो पहले ही की जा चुकी है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। वह प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के कई पैराग्राफ का हवाला देते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के मद्देनजर, रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपराध के बारे में खुलासा किया है और हलफनामा दाखिल करने के माध्यम से इसे रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।

7. श्री मनोज कुमार, राज्य की ओर से उपस्थित जीए-III के विद्वान प्रस्तुत करते हैं कि राज्य ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया है

> और राज्य द्वारा मामलों की उचित अनुसंधान की जा रही है। वह राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे का भी उल्लेख करता है और प्रस्तुत करता है कि राज्य द्वारा मामले की ठीक से अनुसंधान की जा रही है। वह आगे निवेदन करते हैं कि इस मामले को कल उठाया जाए।

8. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किसी भी याचिका को वापस लेने की अनुमति देने में बहुत उदार हैं और केवल दोनों पक्षों की सहमति पर, बिना किसी जांच के वापसी की अनुमति दी जा रही है। न्यायालय मामलों को वापस लेने के खिलाफ नहीं है, हालांकि, यह अदालतों द्वारा जांच के अधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों द्वारा बिना कोई कारण बताए गंभीर आरोपों के मामलों को वापस लेने पर भी चिंता व्यक्त की गई थी।

9. प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाबी हलफनामों के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय को देखते हुए, अदालत ने पाया कि राज्य

के उच्चाधिकारियों के खिलाफ कई सामग्रियां हैं और आईए संख्या 7438/2023 के माध्यम से उक्त वापसी याचिका, प्रथम दृष्टया एक व्यक्ति द्वारा मजबूर होने पर प्रतीत होती है, जो पर्दे के पीछे है।

10. आई.ए. में किए गए कथनों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि दो अधिवक्ताओं, जिन्होंने पहले रिट याचिका दायर की थी, को भी इस याचिकाकर्ता द्वारा नहीं बख्शा गया है और उसने बिना किसी कारण के उनके खिलाफ आरोप लगाने की कोशिश की है। न्यायालय ने वकालतनामा की जांच की है और साहिबगंज जेल के जेलर द्वारा वकालतनामा विधिवत प्रमाणित किया गया है, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के उकसाने पर, जो पर्दे के पीछे है, वर्तमान आई.ए.

11. उपरोक्त के मद्देनजर, आईए संख्या 7438/2023 में की गई प्रार्थना, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है, अदालत इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार, उक्त आईए में की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है।

12. प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश होने वाले जीए-III विद्वान श्री मनोज कुमार के अनुरोध पर, इस मामले को 18.08.2023 को पेश होने दें।

13. श्री अनिल कुमार, विद्वान ए.एस.जी.आई उनकी प्रस्तुति के मद्देनजर शपथ पत्र दायर कर सकते हैं।

13. याचिकाकर्ता के खिलाफ धमकी देने के आरोप को देखते हुए, प्रतिवादी-राज्य याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा।

43. आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 को 18.08.2023 को सूचीबद्ध किया गया था। विद्वान समन्वय पीठ ने मामले के पूरे पहलू पर विचार किया है, अर्थात, प्राथमिकी का पंजीकरण एससी/एसटी साहिबगंज वाद संख्या 06/2022 है, जो साहिबगंज जिले में आने वाले क्षेत्र में अवैध खनन के मुद्दे

को उजागर करने से संबंधित है, जिसे निम्बू पहाड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन जहां तक अवैध खनन के मुद्दे का संबंध है, जांच में कोई उचित प्रगति नहीं हुई है।

44. उक्त रिट याचिका में, राज्य उपस्थित हुआ है और सीबीआई को अंतरवर्ती सौंपने का जोरदार विरोध किया है। विद्वान समन्वय पीठ ने उस वकील के आचरण पर ध्यान दिया है जिसने रिट याचिका वापस लेने के लिए अंतरवर्ती आवेदन दायर किया है और दिनांक 18.08.2023 के निर्णय के पैराग्राफ 17 और 18 में इसका संदर्भ देकर, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 पर इस आशय का निष्कर्ष निकाला गया है कि साहिबगंज जिले में अवैध खनन की पर्याप्त सामग्री है, वह भी पंकज मिश्रा के इशारे पर (ख) जहां तक अवैध खनन का संबंध है, अनुसंधान केवल दिखावा है।

45. जवाबी हलफनामे में लगाए गए आरोप को इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ द्वारा नोट किया गया है जैसा कि जवाबी हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि इस याचिकाकर्ता के मोबाइल का स्थान कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु में पाया गया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने बिनोद प्रसाद के उक्त मोबाइल के बारे में पाया है जो बेंगलुरु का निवासी है, जिससे पता चलता है कि राज्य पुलिस आरोपी व्यक्ति को बचा रही है।

46. इसके अलावा, परिवाद पत्र में लगाए गए आरोप के रूप में, जो उपायुक्त, साहिबगंज और अन्य अधिकारियों के खिलाफ है और इसलिए, न्यायालय *प्रथम दृष्टया* इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राज्य पुलिस मामले की सही दिशा में जांच करने से कतरा रही है।

47. विद्वान समन्वय पीठ ने फिर से अंतरवर्ती आवेदन दायर करने के तथ्य को दोहराया है

> रिट याचिका वापस लेने के लिए पहले के वकील से एनओसी लेने के बाद एक अन्य वकील द्वारा आईए संख्या 7438/2023 और, जैसा कि दिनांक 18.08.2023 के आदेश में चर्चा की गई थी, उक्त अंतरवर्ती आवेदन को रिट याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं देकर खारिज कर दिया गया था।

48. विद्वान समन्वय पीठ ने यह भी ध्यान में रखा है कि याचिकाकर्ता, अर्थात् बिजय हांसदा को शस्त्र अधिनियम के दो मामलों में आरोपी बनाया गया था, जब याचिकाकर्ता के शिकायत मामले को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए विद्वान अदालत द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था और वह जेल में सड़ रहा था और उस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता के वकालतनामा को प्रमाणित किया गया था।

जेलर, साहिबगंज जेल ने पैरवीकर के निर्देश पर वर्तमान रिट याचिका दायर की है और अचानक उक्त अंतरवर्ती आवेदन दायर किया गया है जिसे समन्वय पीठ द्वारा लिया गया है क्योंकि पर्दे के पीछे ऐसे व्यक्ति हैं जो याचिकाकर्ता के पीछे रिट याचिका वापस लेने के लिए हैं और उक्त आदेश को देखते हुए, इस न्यायालय ने झारखंड राज्य द्वारा याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का निर्देश दिया है।

49. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पूर्वोक्त आदेश में उल्लिखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के बाद, निदेशक, सीबीआई को इस याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों के आचरण की प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश देते हुए उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया है क्योंकि उन्होंने एन.ओ.सी. प्राप्त करके एक नए अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पर दायर रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है।

50. न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से जांच के संबंध में भी निर्देश दिया है, जिसे कानून के अनुसार आयोजित करने का निर्देश दिया गया था और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर जल्द से जल्द निर्णित किया जाएगा।

51. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने प्रारंभिक जांच करने का आदेश पारित किया इस निर्देश के साथ कि सीबीआई द्वारा संपर्क किये जाने पर राज्य मशीनरी के साथ प्रवर्तन निदेशालय पूर्ण सहयोग करेंगे

52. उपर्युक्त आदेश में यह भी निदेश पारित किया गया है कि एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने और इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई का चयन करने के

लिए स्वतंत्र होगा। यदि निदेशक, सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है, तो वह इस आशय का उचित आदेश पारित कर सकता है, तैयार संदर्भ के लिए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 18.08.2023 को आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में पारित उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को यहां संदर्भित करने की आवश्यकता है जो इसके तहत इस प्रकार है: -

> 18. आपराधिक रिट याचिका संख्या 156/2020 में, मुद्दा बरहरवा टोल प्लाजा की निविदा के संबंध में था और बरहरवा टोल प्लाजा के संबंध में अब तक जांच के लिए प्रार्थना की गई थी बरहरवा थाना कांड संख्या 85/2020 और उस मामले में, दिनांक 06.12.2022 के आदेश द्वारा, केवल प्रवर्तन निदेशालय को पक्षकार बनाया गया था, जिसे चुनौती दी गई थी, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। मौजूदा मामले में, यह विषय वस्तु नहीं है और इसे देखते हुए, आपराधिक रिट याचिका संख्या 156/2020 का वर्तमान मामले से कोई लेना-देना नहीं है। रिट याचिका में, रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 16 में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने प्रवर्तन निदेशालय का समर्थन किया है और अपना बयान दिया है जो बताता है कि वास्तव में रिट याचिका में प्रार्थना की गई थी, हालांकि, अचानक ही, रिट याचिका वापस लेने के लिए आईए दायर किया गया था, एवं डोरंडा थाने में शिकायत,जो आईए के साथ संलग्न है। स्पष्ट रूप से सुझाव है कि कोई याचिकाकर्ता को केवल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र की गई सामग्री को विफल करने के लिए रिट याचिका वापस लेने के लिए मजबूर कर रहा है।
>
> 19. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, न्यायालय ने पाया कि साहिबगंज जिले में अवैध खनन की पर्याप्त सामग्री है

वह भी पंकज मिश्रा और अन्य के इशारे पर और यदि ऐसी सामग्री रिकॉर्ड में है, तो न्यायालय प्रतिवादी राज्य झारखंड द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के मद्देनजर पाता है कि जहां तक अवैध खनन का संबंध है, जांच केवल एक दिखावा है। राज्य के जवाबी हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि इस याचिकाकर्ता के मोबाइल का स्थान कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में पाया गया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने बिनोद प्रसाद के उक्त मोबाइल के बारे में पाया है जो बेंगलुरु का निवासी है, जिससे पता चलता है कि राज्य पुलिस आरोपी व्यक्ति को बचा रही है। शिकायत में साहिबगंज के उपयुक्त और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया गया है और इसीलिए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य पुलिस मामले की सही दिशा में जांच करने से कतरा रही है और इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने पाया कि आईए संख्या 7438/2023 एक अन्य वकील द्वारा रिट याचिका वापस लेने और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए पहले के वकील से एनओसी लेने के बाद दायर किया गया था दिनांक 17.8.2023 के आदेश में किए गए उक्त आईए को खारिज कर दिया गया था और न्यायालय ने रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति नहीं दी है और उस आदेश की सामग्री को पहले ही उद्धृत किया जा चुका है (सुप्रा)। इसके अलावा इस याचिकाकर्ता को शस्त्र अधिनियम के दो मामलों में आरोपी बनाया गया था जब याचिकाकर्ता के शिकायत मामले को प्राथमिकी के पंजीकरण के लिए विद्वान अदालत द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था और वह जेल में सड़ रहा था और उस अवधि के दौरान, पैरवी कार के निर्देश पर साहिबगंज जेलर के वकालतनामा को प्रमाणित किया गया था, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है और अचानक, उक्त आईए दायर किया गया था जो दर्शाता है कि पर्दे के पीछे ऐसे व्यक्ति हैं, जो

याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका वापस लेने के पीछे हैं और उक्त आदेश के मद्देनजर, इस न्यायालय ने झारखंड राज्य द्वारा याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार, केवल उक्त आईए पर वह भी एक नए वकालतनामा पर एन.ओ.सी प्राप्त करने के बाद रिट याचिका वापस लेने के लिए उचित नहीं था और न्यायालय ने पाया कि सभी प्रयास केवल प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को विफल करने के लिए किए जा रहे थे जैसे कि अपराध की आय अनुसूचित अपराध से प्राप्त हुई है और पुलिस द्वारा दर्ज मामले में साबित नहीं हुई है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला विफल हो जाएगा और यही कार्य-प्रणाली है और इन सभी चीजों के खिलाफ कानूनी दिमाग होना चाहिए जो इस मामले में हुआ है। जहां तक पैरवी कार द्वारा शपथ पत्र के संबंध में तर्क का संबंध है

जहां तक उत्तरदाता राज्य झारखंड की ओर से है, उक्त तर्क देर से लिया गया है और यहां तक कि उत्तरदाता राज्य झारखंड द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में भी कोई कथन नहीं है। यह सर्वविदित है कि झारखंड उच्च न्यायालय नियम, 2001 के अनुसार कि आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को हलफनामा दायर करने की अनुमति नहीं है और केवल पैरबिकार को हलफनामा देने की अनुमति है और वर्तमान मामला दायर करने के समय याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में था और यही कारण है कि वकालतनामा साहिबगंज जेल के जेलर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। पक्षकारों के बीच शपथपत्रों का आदान-प्रदान पहले ही किया जा चुका है और केवल तकनीकी आधार पर यह न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय प्रदान करने में स्वयं को रोक नहीं सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के रिट क्षेत्राधिकार का न्यायालय होने के नाते और तदनुसार, हलफनामे के संबंध में उत्तरदाता राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान ए.ए.जी.-II श्री सचिन कुमार के इस तर्क को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाता है। श्री सचिन कुमार, विद्वान ए.ए.जी.-II द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों की पंक्ति विवाद में नहीं है और यह न्यायालय इस तथ्य के बारे में सचेत है कि नियमित तरीके से या केवल कुछ हलफनामे पर किसी विशेष मामले को किसी विशेष एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

श्री राम ***जानकी जी स्थान तपोवन मंदिर और अन्य बनाम झारखंड राज्य (सुप्रा) के मामले में विद्वान ए.ए.जी.-II द्वारा भरोसा किए गए मामले मे*** विवाद श्री श्री राम जानकी जी ***स्थान तपोवन मंदिर (सुप्रा) के देवता की संपत्ति के संबंध में था*** और उक्त संपत्ति को बनाए रखने के लिए ट्रस्ट थे और उस पृष्ठभूमि में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय

ने वह आदेश पारित किया है और माना है कि सीबीआई जांच का कोई मामला नहीं बनता है। वर्तमान मामले के तथ्य अन्यथा हैं जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। ***पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों और अन्य के संरक्षण पर समिति (सुप्रा)*** के मामले में, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया है, विवाद में नहीं है और मामले को सीबीआई को सौंपने का सिद्धांत उस मामले में और साथ ही संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में तय किया गया है जिसमें पैराग्राफ संख्या 68 और 69 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> 68. इस प्रकार, संवैधानिक योजना के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने के बाद, हम निम्नानुसार निष्कर्ष +
>
> अड़सठ. निकालते हैं:

(१) संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार अंतर्निहित हैं और इन्हें किसी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी कानून जो ऐसे अधिकारों को निरस्त या कम करता है, मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन होगा। भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर कानून के वास्तविक प्रभाव और प्रभाव को यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह मूल संरचना को नष्ट करता है या नहीं।

(२) संविधान का अनुच्छेद 21 अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर व्यक्तियों को उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बचाने का प्रयास करता है। उक्त अनुच्छेद अपने व्यापक अनुप्रयोग में न केवल अभियुक्त के अधिकारों को लागू करता है, बल्कि पीड़ित के अधिकारों को भी अपने दायरे में लेता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह संज्ञेय अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच के लिए प्रदान करने वाले नागरिक के मानवाधिकारों को लागू करे, जिसमें उसके अपने अधिकारी शामिल हो सकते हैं। कुछ स्थितियों में अपराध का गवाह भी मांग सकता है और उसे राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(३) अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त संवैधानिक योजना और अधिकार क्षेत्र और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग होने के मद्देनजर, संसद का कोई भी अधिनियम मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों को बाहर या कम नहीं कर सकता है। वास्तव में, भाग III और

संविधान के अन्य भागों में सन्निहित संविधान के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से विषय-वस्तु प्रदान करने के लिए ऐसी शक्ति आवश्यक है। इसके अलावा, एक संघीय संविधान में, संसद और राज्य विधानमंडल के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में विधायी शक्तियों पर सीमा शामिल है और इसलिए, इसके लिए संसद के अलावा एक अन्य प्राधिकरण की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। न्यायिक समीक्षा न केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को प्रभावी बनाने के लिए अंतिम मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, बल्कि प्रत्येक द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन दिखाना भी आवश्यक है

। इसलिए, लॉर्ड स्टेन के शब्दों को उधार लेने के लिए, न्यायिक समीक्षा "शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों, कानून के शासन, संवैधानिकता के सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा की पहुंच" के संयोजन से उचित है।

(४) यदि किसी विधायी कार्रवाई से संघीय ढांचे का उल्लंघन होता है, तो संविधान यह सुनिश्चित करके संघीय ढांचे की रक्षा करने का ध्यान रखता है कि न्यायालय संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार के रूप में कार्य करें और जब भी उल्लंघन का प्रयास किया जाता है, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उपाय प्रदान करें। इन परिस्थितियों में, संविधान को बनाए रखने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 32 या 226 के तहत शक्ति के प्रयोग में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी निर्देश को संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

(५) संविधान द्वारा संसद पर प्रतिबंध और अधिनियमन के अंतर्गत संसद द्वारा कार्यपालिका पर निर्बंधन, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन न्यायपालिका की शक्ति पर निर्बंधन नहीं है।

(६) यदि एक ओर सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 2 और दूसरी ओर सूची । की प्रविष्टि 2-क और प्रविष्टि 80 के अनुसार संबंधित राज्य द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के अध्यधीन किसी अन्य अभिकरण द्वारा अन्वेषण अनुमेय है तो कोई कारण नहीं है कि अपवादात्मक स्थिति में न्यायालय को उसी शक्ति का प्रयोग करने से रोका जाएगा जो संघ क़ानून के प्रावधानों के संदर्भ में प्रयोग कर सकता

है। हमारी राय में, संवैधानिक अदालतों द्वारा इस तरह की शक्ति का प्रयोग शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेगा। वास्तव में, यदि ऐसी स्थिति में न्यायालय राहत देने में विफल रहता है, तो यह अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल होगा।

(७) जब विशेष पुलिस अधिनियम स्वयं यह प्रावधान करता है कि राज्य की सहमति के अधीन, सीबीआई उस अपराध के संबंध में जांच कर सकती है जो अन्यथा राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है और सीबीआई को राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच करने का निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति

विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 द्वारा संविधान को छीना, कम या हल्का नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान होने के बावजूद, संघ की शक्तियों पर विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग, हमारी राय में, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत या संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा।

69. अंतिम विश्लेषण में, संदर्भित प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सीबीआई को उस राज्य की सहमति के बिना किसी राज्य के क्षेत्र के भीतर कथित रूप से किए गए संज्ञेय अपराध की जांच करने का निर्देश न तो संविधान के संघीय ढांचे का अतिक्रमण करेगा और न ही शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा और वैध होगा कानून में। नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक होने के नाते, इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न केवल शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी है, जो सामान्य रूप से भाग III द्वारा और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उत्साहपूर्वक और सतर्कता से गारंटीकृत है।

20. उस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच को उचित तरीके से नहीं मानते हुए और साथ ही उस मामले में उच्च अधिकारियों को शामिल किया था, मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था और उस

अनुपात में, वर्तमान मामला भी उसी पायदान पर है क्योंकि उच्च अधिकारियों को भी एक पंकज मिश्रा के साथ मिलीभगत कहा जाता है जो साहिबगंज जिले में पत्थर खनन के किंग-पिन हैं। बिमल ***गुरुंग (सुप्रा) के मामले*** **में विद्वान ए.ए.जी.-II श्री सचिन कुमार द्वारा भरोसा किए गए मामले में,** मामला अन्यथा था और मामला गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के आंदोलन से उत्पन्न हुआ था और संपत्ति का विनाश उस मामले में विषय वस्तु थी और उस परिदृश्य में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वह आदेश और तथ्यों को पारित किया है वर्तमान मामला अन्यथा है और वह मामला प्रतिवादी राज्य झारखंड की मदद नहीं कर रहा है। अब तक इस मामले पर श्री सचिन कुमार, विद्वान ए.ए.जी.-II द्वारा

के.वी. राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक, सीबी, सीआईडी, दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई और अन्य (सुप्रा) का संबंध है, उस मामले में उच्च न्यायालय ने पहले ही मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है और उसके बाद दूसरी याचिका में यह निर्देश जारी किया गया था और उस पृष्ठभूमि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वह आदेश पारित किया है जो वर्तमान रिट याचिका का विषय नहीं है। ***रॉयडेन हेरोल्ड बुथेलो और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (सुप्रा)*** के मामले में प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया, तथ्य अन्यथा थे। उस मामले में, मामला न्यायिक कार्यवाही में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार किए जाने वाले साक्ष्य के संबंध में था और इसीलिए, वह आदेश पारित किया गया था और वर्तमान मामले के तथ्य अन्यथा हैं। श्री सचिन कुमार द्वारा भरोसा किए गए निर्णय में, ***अनंत थानुर कर्मसे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (सुप्रा)*** के मामले में विद्वान ए.ए.जी.-II ने भी उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 42 और 48 में संवैधानिक न्यायालय की शक्ति के बारे में माना है जो नीचे उद्धृत हैं:

> 42. धर्म पाल में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना [धर्म पाल बनाम हरियाणा राज्य, (2016)
>
> 4 एससीसी 160: (2016) 2 एससीसी (सीआरआई) 259] और भारती तमांग [भारती तमांग बनाम भारत संघ (2013) 15 एससीसी 578 (2014) 6 एससीसी (सीआरआई) 566] और पूर्ण न्याय करने के लिए तथा निष्पक्ष अन्वेषण और निष्पक्ष विचारण को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक न्यायालय आरोप पत्र दायर किए जाने और आरोप विरचित किए जाने के बाद भी आगे जांच/पुन जांच/नए सिरे से का आदेश दे सकते हैं।

यदि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया और यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि एक बार आरोप पत्र दायर करने और आरोप तय किए जाने के बाद, आगे की जांच/पुन: जांच/नए सिरे से जांच के लिए कोई आदेश स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उस मामले में, अभियुक्त यह देख सकता है कि किसी भी निष्पक्ष जांच/निष्पक्ष सुनवाई से बचने के लिए आरोप तय किए गए हैं। इससे न्याय का उपहास होगा।

48. जैसा कि यह हो सकता है, यहां तक कि राज्य जांच एजेंसी के अनुसार, आगे की जांच की आवश्यकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में देखा और माना गया है, पीड़ित को निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार है। इसलिए, केवल आरोप-पत्र दाखिल करने और आरोप तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

यदि तथ्यों की आवश्यकता हो तो आरोप आगे की अनुसंधान/पुनः अनुसंधान /नए सिरे से अनुसंधान का आदेश देने में बाधा नहीं बन सकते।

30. ऊपर चर्चा किए गए उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के आचरण की प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया जाता है तो यह पर्याप्त रूप से पूरा होगा क्योंकि उन्होंने वकालतनामा पर रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है एन.ओ.सी. और इसके मद्देनजर, रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से जांच के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना भी उचित होगी। ऐसी प्रारंभिक जांच कानून के अनुसार की जाएगी और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो जाएगी।

32. यह न्यायालय आशा करता है और विश्वास करता है कि प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्य से नियुक्त अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित सीबीआईआई द्वारा संपर्क की जाने वाली व्यक्तिगत एजेंसियों से उचित विचार प्राप्त होगा। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने और इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद, निदेशक, सीबीआई कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि निदेशक, सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है, तो वह इस आशय का उचित आदेश पारित कर सकता है।

53. प्रारंभिक जांच शुरू हुई और निदेशक, सीबीआई के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उस मोड़ पर सीबीआई के माध्यम से भारत संघ ने आपराधिक विविध याचिका संख्या 3378/2023 के रूप में एक आपराधिक विविध याचिका दायर की, जिसमें एससी/एसटी साहिबगंज थाना कांड संख्या 06/2022 के संबंध में

डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2023 में संशोधन के लिए इस आशय की एक आपराधिक विविध याचिका दायर की गई कि नियमित मामला स्थापित करने का निर्देश दिया जा सकता है, चूंकि, प्रारम्भिक जांच करने के दौरान संज्ञेय अपराध पाया गया है।

54. समन्वय विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैराग्राफ 32 में निहित निर्देश/अवलोकन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 03.11.2023 के आदेश के माध्यम से, जिसमें समन्वयक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आशय का आदेश पारित किया है : *"यह न्यायालय आशा करता है और विश्वास करता है कि प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्य से नियुक्त अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित सीबीआई, उनसे संपर्क करने वाली व्यक्तिगत एजेंसियों से उचित विचार प्राप्त होगा। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने और इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद, निदेशक, सीबीआई कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि निदेशक, सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है, तो वह इस आशय का उचित आदेश पारित कर सकते हैं"* ने दिनांक 18.08.2023 के आदेश में संशोधन के लिए दायर उक्त याचिका को गलत माना है और तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई थी।

55. तत्पश्चात्, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने RC0242023S0011 एक नियमित मामला शुरू किया है। सीबीआई द्वारा उपरोक्त नियमित मामले के अनुसरण में अनुसंधान शुरू की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2023 आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में पारित आदेश के संदर्भ में स्थापित किया गया है। जब जांच आगे बढ़ी, तो वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

56. याचिका पर पहली बार 19.01.2024 को एक अन्य पीठ (श्री न्यायमूर्ति राजेश कुमार) द्वारा सुनवाई की गई थी। समन्वय पीठ ने रिट याचिका में की गई प्रार्थना सहित पक्षों की ओर से दिए गए तर्क पर ध्यान दिया है। पक्षकारों की संयुक्त प्रार्थना पर मामले को स्थगित कर दिया गया और इसे 09.02.2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

57. समन्वय पीठ ने इस आशय का आगे आदेश पारित किया है कि सीबीआई अगले आदेश तक जांच के साथ आगे नहीं बढ़ेगी, तैयार संदर्भ के लिए, पूर्वोक्त आदेश को इस प्रकार संदर्भित किया जा रहा है: -

> एक. निम्नलिखित राहतों के लिए तत्काल रिट आवेदन दायर किया गया है: -
>
> > "(1) प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट या कोई अन्य उपयुक्त आदेश, रिट निर्देश जारी करना जो सीबीआई, एसीबी, रांची के आरसी वाद संख्या 0242023S0011 दिनांक 20.11.2023 को आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में पारित झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2023 के आधार पर दर्ज किया गया है, जहां तक सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 का स्पष्ट उल्लंघन है
> >
> > (ख) के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने और प्रतिवादियों द्वारा मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार से कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई है।
> >
> > (२) घोषणा रिट की प्रकृति में घोषणा की रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, कि प्रतिवादी की शक्ति जहां तक सीधे धारा 6 का उल्लंघन है और संघवाद की मूल संरचना का

उल्लंघन करती है और शक्तियों का पृथक्करण करती है, और इसलिए प्रतिवादी द्वारा ऐसी जांच, जांच आदि केवल राज्य एजेंसियों/राज्य के अनुरोध पर की जा सकती है

या माननीय संवैधानिक न्यायालय के निर्देशों के तहत ।

(३) आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में पारित दिनांक 18.08.2023 को सीबीआई, एसीबी, रांची के आरसी वाद संख्या 0242023S0011 होने के संबंध में आगे की जांच पर अंतरिम रोक का आदेश जारी करें।

(४) इस तरह के अन्य और आगे के आदेश या राहत को पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझ सकता है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पहले एक मामला साहेबगंज एससी / पी.एस. वाद संख्या 06 2022 दिनांक 01.12.2022 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 323, 500, 504, 506, 120-बी और 34 के तहत अपराध के लिए, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत, जेएमएमसी के नियम 04/54 के तहत। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)
के अंतर्गत बिजय हांसदा द्वारा दर्ज किया गया है। उक्त प्राथमिकी शिकायत याचिका के आधार पर दर्ज की गई है। इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए आपराधिक रिट याचिका (सीआर) संख्या 665/2022 (अनुलग्नक-3) एक रिट याचिका दायर की गई है।

इस बीच, एक अंतरवर्ती आवेदन किया जा रहा है आईए संख्या 7438/2023 उसी आपराधिक रिट आवेदन को वापस लेने के लिए दायर किया गया है, जो आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 है, लेकिन उक्त अंतरवर्ती आवेदन में की गई प्रार्थना को दिनांक 17.08.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। अदालत ने सीबीआई को दिनांक 18.08.2023 के आदेश के तहत प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा था, विशेष रूप से इस आरोप को जानने के लिए कि शिकायतकर्ता पर दबाव डाला जा रहा है। आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2023 के प्रासंगिक अंश यहां नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

> "30. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, यहां ऊपर चर्चा की गई है, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह पर्याप्त रूप से सेवा की जाएगी यदि निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)को इस याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के आचरण की प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि उन्होंने एनओसी प्राप्त करने के माध्यम से एक नए वकील द्वारा दायर वकालतनामा पर रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है और इसके मद्देनजर, रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से जांच के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना भी उचित होगी। इस तरह के प्रारंभिक

जांच कानून के अनुसार आयोजित की जाएगी और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर जितनी जल्दी हो सके निष्कर्ष निकाला जाएगा।

31. याचिकाकर्ता को साहिबगंज पुलिस द्वारा संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि उसकी जान को खतरा है।

32. यह न्यायालय आशा और विश्वास करता है कि प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्य से नियुक्त अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित सीबीआईआई द्वारा संपर्क की जाने वाली व्यक्तिगत एजेंसियों से उचित विचार प्राप्त होगा। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने और इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद, निदेशक, सीबीआई कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि निदेशक, सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है, तो वह इस आशय का उचित आदेश पारित कर सकता है।

33. उपरोक्त तथ्यों और कारणों और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त शर्तों में आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 की अनुमति दी जाती है और इसका निपटान किया जाता है।

34. I.A. यदि कोई लंबित है तो उसका निपटान हो जाएगा।

35. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित विद्वान ए.एस.जी.आई श्री अनिल कुमार और वे सीबीआई का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने इस आदेश को निदेशक, सीबीआई को सूचित करने का अनुरोध किया है।

36. नतीजतन, इस याचिका का निपटारा किया जाता है।

3. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रारंभिक जांच करने के बाद सीबीआई ने आपराधिक विविध याचिका संख्या 3378/2023 (अनुलग्नक-5)। दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उक्त आपराधिक विविध याचिका दिनांक 03.11.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश निम्नानुसार है: -

> "यह याचिका विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- I, साहिबगंज की अदालत में लंबित एससी/एसटी साहिबगंज पीएस वाद संख्या 06/2022 के संबंध में आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2023 के संशोधन के लिए दायर की गई है।

2. दिनांक 18.08.2023 के आदेश द्वारा, 2022 की डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665 को उक्त निर्णय के पैरा- 32 में निर्देश के माध्यम से निपटाया गया था, जो निम्नानुसार है: -

> "32. यह न्यायालय आशा और विश्वास करता है कि प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्य से नियुक्त अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित सीबीआईआई द्वारा संपर्क की जाने वाली व्यक्तिगत एजेंसियों से उचित विचार प्राप्त होगा। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने और इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद, निदेशक, सीबीआई कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि निदेशक,
>
> सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है, वह इस आशय का उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

3. याचिकाकर्ता-सीबीआई की ओर से पेश होने वाले श्री अनिल कुमार, विद्वान ए.एस.जी.आई प्रस्तुत करते हैं कि प्रारंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करने और जांच को अपने हाथ में लेने का कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त आदेश में संशोधन की आवश्यकता है।

4. श्री राजीव रंजन, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि एक बार आपराधिक मामले का निपटारा हो जाने के बाद, अदालत सीआरपीसी की धारा 362 के मद्देनजर कोई आदेश पारित करने से रोक देती है। वह प्रस्तुत करता है कि

आदेश पहले से ही है और इसे संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5.उपरोक्त निर्देश के मद्देनजर, जिसे यहां ऊपर उद्धृत किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका गलत है। तदनुसार, यह याचिका खारिज की जाती है।

इसके बाद, सीबीआई द्वारा दिनांक 20.11.2023 को 20.11.2023 की प्राथमिकी संख्या RC0242023S0011 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसे आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 120-बी, 379, 323, 500, 504, 506, शस्त्र अधिनियम की धारा 27, एससी/एसटी की धारा 3(1)(एस) के तहत दर्ज किया गया है। अधिनियम और जेएमएमसी नियम, 2004 के नियम 04/54 के तहत।

4. इसके अलावा, झारखंड राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्राथमिकी के दर्ज होने पर यह दलील देते हुए हमला किया है कि यह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्योंकि सीबीआई केवल राज्य के विषयों में

राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति या संवैधानिक न्यायालय द्वारा एक प्राधिकृत करने पर, अन्यथा नहीं। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि अदालत ने केवल कुछ आरोपों पर जांच के लिए कहा था। विचाराधीन प्राथमिकी को जांच के लिए सीबीआई को कभी नहीं सौंपा गया.

5.आगे यह तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी का दाखिला पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अन्यथा भी, यह पक्षकारों के बीच एक प्रकार का निजी विवाद है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को परेशान किए जाने का आरोप है। इसके अलावा, सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को राज्य द्वारा दिनांक 05 नवंबर, 2020 के आदेश के तहत पहले ही वापस ले लिया गया है। इस प्रकार, न तो राज्य सरकार की सहमति है और न ही संवैधानिक न्यायालय द्वारा कोई प्राधिकरण है। वर्तमान रिट आवेदन में शामिल एकमात्र मुद्दा यह है कि "क्या सीबीआई को संवैधानिक न्यायालय द्वारा जांच को संभालने के लिए अधिकृत किया गया है, जैसा कि प्राथमिकी द्वारा शुरू किया गया है, एससी/एसटी थाना कांड संख्या 06/2022 दिनांक 01.12.2022 है या नहीं। उपरोक्त आधार पर, जांच पर रोक लगाने के रूप में अंतरिम संरक्षण के लिए प्रार्थना की गई है।

6. सीबीआई के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए अनुरोध का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि अदालत ने प्रारंभिक जांच करने के लिए सीबीआई को स्पष्ट रूप से अधिकृत किया है और उसके बाद रिपोर्ट को निदेशक, सीबीआई के समक्ष रखने का

निर्देश दिया गया है और निदेशक, सीबीआई को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है।

7. इसके अलावा, सीबीआई के विद्वान वकील द्वारा आपत्ति उठाई गई है कि राज्य सरकार के पास वर्तमान रिट आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार प्रभावित नहीं है और इसका उत्तर राज्य/याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह कहते हुए दिया गया है कि यह राज्य की विषय वस्तु है जिसे सीबीआई द्वारा हड़पा जा रहा है और अन्यथा यह कानून में स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, राज्य प्रभावित व्यक्ति है।

8. जैसा कि संयुक्त रूप से प्रार्थना की गई थी, इस मामले को 09.02.2024 को रखा जाए ।

9. अगले आदेश तक सीबीआई जांच को आगे नहीं बढ़ाएगी।

58. इस मामले की सुनवाई 09.02.2024 को हुई लेकिन श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई प्रार्थना पर,

जो श्री राजीव रंजन, विद्वान महाधिवक्ता की सहायता से वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित हुए थे और भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सहमति से, मामले को 16.02.2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था और इस तरह मामले को आज, यानी 16.02.2024 को पोस्ट किया गया है।

59. श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव रंजन, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त आभासी मोड के माध्यम से उपस्थित हुए और निम्नलिखित मुद्दों को उठाया: -

(१) यह पूरा मामला दो निजी पक्षों के बीच का विवाद है जो शिकायत मामले के दाखिला से स्पष्ट होगा जिसे धारा 156 (3) सीआरपीसी के प्रावधान के तहत पुलिस को भेजा गया था और बाद में उक्त शिकायत मामले को एससी/एसटी साहिबगंज थाना केस संख्या 06/2022 के रूप में स्थापित किया गया है।

इसलिए, आधार यह लिया गया है कि उक्त शिकायत मामले की सामग्री स्पष्ट करती है कि यह राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई कथित गलती के संबंध में व्यक्ति की शिकायत है, जो शिकायतकर्ता के अनुसार, अवैध खनन में रोक लगाने में विफल रहे हैं और इसलिए आरोप की प्रकृति को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का मामला नहीं माना जा सकता है।

(२) सीबीआई जांच संवैधानिक न्यायालयों द्वारा निर्देशित की जानी है, या तो उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या उसके अनुच्छेद 32 के प्रावधान के तहत केवल दुर्लभतम मामलों में है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य और अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णयों में निपटाया गया है ***3 एससीसी 542*** (2008) (पैरा 41) ।

(३) समन्वय पीठ ने प्रारंभिक जांच करने का आदेश पारित करते समय अपराधियों के दो समूहों के *परस्पर* विवाद के तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में नहीं लाया है और इसलिए, प्रारंभिक जांच का आदेश देने का निर्देश दिया गया है।

(४) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी जांच कर सकता है लेकिन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत यथा अपेक्षित राज्य सरकार की मंजूरी होने पर । लेकिन, यहां राज्य सरकार द्वारा कोई मंजूरी नहीं है और इसलिए, आपराधिक भाग के संबंध में सीबीआई द्वारा कोई जांच नहीं की जा सकती है जो वर्तमान रिट याचिका का विषय है।

(५) राज्य की ओर से दायर हलफनामा, याचिकाकर्ता ने सीबीआई द्वारा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर

न्यायालय को यह समझाने का आदेश दिया गया कि सीबीआई जांच के लिए आवश्यक सामग्री को उपलब्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जांच करने पर भी सीबीआई द्वारा यह सामने आया है कि यह दो निजी पक्षों के बीच परस्पर विवाद है।

(६) यह आगे स्पष्ट होगा कि रिट याचिका के याचिकाकर्ता ने आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 होने के नाते रिट याचिका वापस लेने का इरादा किया था और वकालतनामा दायर करने के माध्यम से वकील के दो सेटों के बीच आरोप और प्रतिआरोप है, जिसे इस अदालत के समन्वयक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा या तो आईए संख्या 7438/2023 या रिट याचिका में आदेश पारित करते समय ध्यान में रखा गया है आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 होने के नाते। यहां तक कि याचिकाकर्ता पर याचिका वापस लेने के लिए जोर देने के उद्देश्य से इसे एक आरोप के रूप में स्वीकार करते हुए, इसे दुर्लभतम मामले के दायरे में आने वाला मामला नहीं कहा जा सकता है जिसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है।

(७) इसके अलावा, विद्वान महाधिवक्ता ने निष्कर्ष तर्क में, नियमित मामले का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है जिसमें यह संदर्भित किया गया है कि आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के अनुसरण में, नियमित मामला स्थापित किया जा रहा है।

यह तर्क आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में समन्वयक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18.08.2023 के आदेश का हवाला देते हुए दिया गया है, जिसमें प्रारंभिक जांच के समापन के बाद नियमित मामला दर्ज करके जांच करने का कोई निर्देश नहीं है और इसलिए, नियमित मामला दर्ज करने का मूल सिद्धांत इस न्यायालय के समन्वयक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के बिल्कुल विपरीत है।

60. याचिकाकर्ता/राज्य के विद्वान वकील ने उपरोक्त आधार के आधार पर प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है क्योंकि पुलिस ने मामले की जांच की है और सीबीआई जैसी विशेष एजेंसी द्वारा जांच करने का कोई कारण नहीं है।

61. उपरोक्त आधार को देखते हुए, पूरी जांच को रद्द करने की प्रार्थना को स्वीकार करने की मांग की गई है।

62. इसके विपरीत, श्री अनिल कुमार, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री चंदना कुमारी द्वारा सहायता प्राप्त, ने याचिकाकर्ता की ओर से उठाये आधारों के खंडन में उपरोक्त आधारों को लेते हुए प्रस्तुत किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है: -

(१) झारखण्ड राज्य के पास की जा रही जांच पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है

चूंकि जांच राज्य के हित में की जा रही है और राज्य के साथ कोई शिकायत नहीं हो सकती है, क्योंकि समन्वयित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश राज्य के हित के विरुद्ध नहीं है, बल्कि, यदि जांच की जाएगी और निष्कर्ष निकाला जाएगा, यह झारखंड राज्य और विशेष रूप से झारखंड राज्य के लोगों के हित में होगा, शिकायत में निर्दिष्ट आरोप को ध्यान में रखते हुए, जो अनियंत्रित अवैध खनन से संबंधित है और यहां तक कि शिकायतकर्ता द्वारा उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक या जिला खनन अधिकारी के समक्ष शिकायत किए जाने के बाद भी, कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उक्त शिकायत मामले के शिकायतकर्ता को भी धमकी दी गई है।

(२) यह तर्क दिया गया है कि खनन प्राकृतिक संसाधन है और राज्य के वित्त का मुख्य स्रोत है और यदि शिकायत के अनुसार कोई अवैध खनन होता है और जब उपयुक्त और खनन विभाग के पदाधिकारी ने ऐसे अवैध खनन से निपटने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, फिर जो अनुसंधान प्रारंभिक जाँच के दौरान आई सामग्री के आधार पर किया जा रहा है, वह राज्य के हित के विरुद्ध कैसे होगा

(३) पंकज मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने, भले ही वह आपराधिक मामले में पक्षकार नहीं था, शिकायत के अनुसार, आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में समन्वय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18.08.2023 के आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सीबीआई

को मामले में प्रारंभिक जांच/जांच करने से रोकने की प्रार्थना के साथ पूरे आदेश को चुनौती दी गई थी। जांच में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक अलग अंतरवर्ती आवेदन दायर करके भी प्रार्थना की गई है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अपील (सीआरएल) संख्या 12087/2023 में पारित दिनांक 04.12.2023 के आदेश के तहत जांच पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।

(४) इसके अलावा, उक्त पंकज मिश्रा द्वारा आपराधिक रिट याचिका के पक्षकार के रूप में कोई पक्षकार नहीं होने के आधार पर जो आधार लिया गया है, उसे भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि अनुसंधान/जांच के चरण में, संबंधित व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए सुनवाई के अवसर का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, मामला अभी भी अंतिम निर्णय के लिए लंबित है और इस बीच, वर्तमान रिट याचिका उसी मुद्दे को उठाते हुए दायर की गई है

अवैध खनन के मामले में सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए हैं लेकिन अब इस बार झारखंड राज्य द्वारा।

(५) झारखण्ड राज्य सीबीआई द्वारा की गई जांच से व्यथित है और उक्त पंकज मिश्र के साथ भी यही स्थिति है, जहां तक समन्वय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का संबंध है और इसलिए यह भी समझा जा सकता है कि झारखंड राज्य और पंकज मिश्रा, जिनके खिलाफ सीधा आरोप लगाया गया है, के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है और उस परिस्थिति में, जो झारखण्ड राज्य के आचरण से स्पष्ट है, सीबीआई जांच आवश्यक है।

63. याचिकाकर्ता झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल द्वारा तर्क दिया गया है इस हद तक कि विद्वान वकील की साजिश या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दो समूहों से संबंधित दो पक्षों के बीच परस्पर विवाद के बारे में तथ्यों को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया होता, अन्यथा वह आदेश पारित नहीं किया गया होता।

64. लेकिन, इस तरह की दलील इस समय उठाने के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उक्त आदेश के औचित्य का निर्णय समन्वय न्यायपीठ द्वारा नहीं किया जा सकता है, अर्थात, वर्तमान एक को, रिट याचिका दायर करके।

65. इसके अतिरिक्त, जहां तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता और औचित्य का संबंध है, वह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

66. यह तर्क दिया गया है कि यदि पूर्वोक्त तर्क को स्वीकार किया जाएगा, तो यह समन्वय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की समीक्षा करने के समान होगा जो बिल्कुल भी संभव नहीं है।

67. यह आधार लिया गया है कि चूंकि प्रारंभिक जांच में संज्ञेय अपराध का मामला सामने आ चुका है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार, मामले को आगे की जांच के लिए एक नियमित मामले के रूप में दर्ज किया जाना है ताकि आम जनता के हित में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।

68. इस न्यायालय ने तब से पक्षकारों के आचरण के संबंध में प्रारंभिक जांच करने के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत आदेश पारित किया है, अर्थात, रिट याचिका को वापस लेने के उद्देश्य से विभिन्न वकीलों की नियुक्ति द्वारा उठाए गए कदम और अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, भले ही उपायुक्त और जिला खनन अधिकारी को घटना के बारे में विधिवत सूचित किया गया हो और जब कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, इसके बाद, शिकायत दर्ज की गई है, फिर ऐसी परिस्थितियों में, नियमित मामले के पंजीकरण या मंजूरी/अनुमति के उद्देश्य से संवैधानिक न्यायालय द्वारा फिर से निर्देश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आवश्यक है।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6।

69. विद्वान ए.एस.जी.आई., ने पूर्वोक्त आधार के आधार पर प्रस्तुत किया है कि वर्तमान रिट याचिका खारिज करने के योग्य है।

70. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं रिट याचिका के अभिवचन एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया

71. यह न्यायालय, वर्तमान रिट याचिका की विषय वस्तु के रूप में इस मुद्दे का उत्तर देने के लिए, निम्नलिखित मुद्दों का उत्तर देना उचित और उचित समझता है: -

(१) क्या एक बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया है और यदि संज्ञेय अपराध करने की सामग्री सामने आई है, तो जांच के लिए एक नियमित मामला दर्ज करने के उद्देश्य से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के प्रावधान के अनुसार राज्य से आगे का निदेश,अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन निदेश की आवश्यकता है?

(२) क्या जांच करने के उद्देश्य से नियमित मामले के पंजीकरण को उस मामले के वर्तमान तथ्यों में अनुचित कहा जा सकता है जिसमें प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शर्तों के अनुसार, लेकिन उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा उच्च मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है- क्या यह झारखंड राज्य के लिए उपलब्ध हो सकता है कि वह सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच करने के लिए मामले को संदर्भित करने के आधार पर सवाल उठाए?

72. चूंकि दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए मुद्दों को एक साथ लेकर तय किया जा रहा है।

73. इस न्यायालय को, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखने से पहले, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के प्रावधान का उल्लेख करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त अधिनियम 1946 के अधिनियम संख्या 25 के आधार पर 19 नवंबर, 1946 को अधिसूचित किया गया है और इसे भारत के संविधान के साथ असंगत नहीं होने के कारण सांविधिक दर्जा प्राप्त है।

74. उपर्युक्त अधिनियम संघ राज्य क्षेत्रों में कतिपय अपराधों की जांच-पड़ताल, उक्त बल के अधीक्षण और प्रशासन के लिए तथा अन्य क्षेत्रों में विस्तार के लिए दिल्ली में एक विशेष पुलिस बल के गठन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

75. 1951 के अधिनियम 3 द्वारा “राज्यों में” शब्दों को हटा दिया गया है। इस अधिनियम को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 कहा गया है जो पूरे भारत में फैला हुआ है। 1956 के अधिनियम 62 द्वारा छोड़े गए भाग बी राज्यों को छोड़कर 1951 के अधिनियम 3 द्वारा किए गए प्रतिस्थापन के आधार पर।

76. अधिनियम, 1946 की धारा 5 और 6 इसमें शामिल मुद्दे के लिए प्रासंगिक है जिसमें अन्य क्षेत्रों में विशेष पुलिस स्थापना की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए राज्य सरकार की सहमति रखने का प्रावधान है, तैयार संदर्भ के लिए, धारा 5 और धारा 6 को यहां संदर्भित करने की आवश्यकता है जो इसके तहत पढ़ें:

> "**5.** (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, किसी राज्य में, जो संघ राज्यक्षेत्र नहीं है, धारा 3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किन्हीं अपराधों या अपराधों की श्रेणियों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार आदेश द्वारा, कर सकेगी।
>
> 2. जब उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा उक्त पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियां और अधिकारिता ऐसे किसी क्षेत्र को दी जाती है तब उसका कोई सदस्य, किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, उस क्षेत्र में किसी पुलिस अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा और इस प्रकार ऐसे कृत्यों का निर्वहन करते समय, उस क्षेत्र के पुलिस बल का सदस्य समझा जाएगा और शक्तियों, कार्यों और विशेषाधिकारों के साथ निहित किया जाएगा और उस पुलिस बल से संबंधित पुलिस अधिकारी की देनदारियों के अधीन होगा।
>
> 3. जहां उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश किसी क्षेत्र के संबंध में किया जाता है वहां उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपनिरीक्षक के रैंक का या उससे ऊपर का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का कोई सदस्य, किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, उस क्षेत्र में किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, अपने स्टेशन की सीमाओं

के भीतर ऐसे अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में समझा जाएगा।

6. शक्तियों और अधिकारिता के प्रयोग के लिए राज्य सरकार की सहमति--धारा 5 में अन्तर्विष्ट कोई बात दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी सदस्य को उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य के किसी क्षेत्र में, जो संघ राज्यक्षेत्र या रेल क्षेत्र नहीं है, शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ बनाने वाली नहीं समझी जाएगी।

77. धारा 5 के उपबंध से यह स्पष्ट है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की शक्ति और क्षेत्राधिकार को देश के अन्य भागों में बढ़ाया गया है लेकिन धारा 6 के अंतर्गत एक उपबंध बनाया गया है जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया है कि धारा 5 में यथा उपलब्ध रोक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के किसी सदस्य को राज्य, जो संघ राज्य क्षेत्र या रेलवे क्षेत्र नहीं है, उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना, जिसका अर्थ है, शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के उद्देश्य से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अनुसार विशेष पुलिस स्थापना को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।

78. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ने शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में एक बाधा डाल दी है, बल्कि, इसे राज्य सरकार की सहमति से किया जाना है। धारा 5 और 6 के तहत शब्द विशेष पुलिस स्थापना द्वारा की जाने वाली शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग है।

79. यह मुद्दा उठाया गया है कि संवैधानिक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, चाहे वह उच्च न्यायालय में

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226के तहत प्रदत् शक्ति या भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ताकि जांच को विशेष पुलिस स्थापना को सौंप दिया जा सके।

80. बिमल गुरुंग बनाम भारत संघ और अन्य ***[(2018) 15 SCC 480]*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इस तरह की जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति दुर्लभ और असाधारण मामलों में होनी चाहिए जहां अदालत को जनता के दिमाग में विश्वास पैदा करने के लिए पार्टियों के बीच न्याय करना आवश्यक लगता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ यहां उद्धृत किया गया है: -

> **"29.** इस प्रकार कानून अच्छी तरह से तय है कि अन्य जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए, जहां अदालत जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए पक्षों के बीच न्याय करना आवश्यक समझती है, या जहां राज्य पुलिस द्वारा जांच में विश्वसनीयता की कमी है। ऐसी शक्ति का प्रयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। *के.वी. राजेंद्रन* बनाम *पुलिस अधीक्षक* [*के.वी. राजेंद्रन* बनाम *पुलिस अधीक्षक*, (2013) 12 एससीसी 480] के अनुसार, इस न्यायालय ने कुछ परिस्थितियों पर ध्यान दिया है, जहां न्यायालय राज्य पुलिस से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसे: (*i*) जहां राज्य प्राधिकरणों के उच्च अधिकारी शामिल हैं, या (*ii*) जहां आरोप स्वयं जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ है, जिससे उन्हें जांच को प्रभावित करने की अनुमति मिलती है, या (*iii*) जहां जांच प्रथम दृष्टया दागी/पक्षपातपूर्ण पाई जाती है।

81. ***पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य*** (2010) 3 एससीसी 571 में, रिपोर्ट किया गया में

\ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने किसी राज्य की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर कथित रूप से किए गए संज्ञेय अपराध के अन्वेषण का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निदेश देने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर विस्तार से विचार किया है और यह मत व्यक्त करते हुए कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, आगाह किया कि न्यायालय को कुछ स्वतःलगाए गए सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 70 को इसके तहत उद्धृत किया गया है: -

> **"70.** मामले से अलग होने से पहले, हम इस बात पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद, कोई भी आदेश पारित करते समय, न्यायालयों को इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्व-अधिरोपित सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त अनुच्छेदों के अधीन शक्ति की प्रचुरता को इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जहां तक किसी मामले में जांच करने के लिए सीबीआई को निदेश जारी करने का प्रश्न है, यद्यपि यह निर्णय करने के लिए कोई लचीले दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बार-बार यह दोहराया गया है कि ऐसा आदेश नेमी मामले के रूप में या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी पक्ष ने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से, सावधानी से और असाधारण परिस्थितियों में किया

जाना चाहिए, जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो सकता है। अन्यथा सीबीआई के पास बड़ी संख्या में मामलों की बाढ़ आ जाएगी और सीमित संसाधनों के साथ, गंभीर मामलों की भी ठीक से जांच करना मुश्किल हो सकता है

और इस प्रक्रिया में असंतोषजनक जांच के साथ अपनी विश्वसनीयता और उद्देश्य खो देते हैं।

82. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक घोषणाओं को पढ़ने से यह स्पष्ट है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि न्यायालय केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही किसी भी जांच को राज्य अनुसंधान एजेंसी से किसी अन्य अनुसंधान एजेंसी को स्थानांतरित करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

83. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा तब किया जा सकता है जब पार्टियों के बीच न्याय करने और जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक हो।

84. केवी राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई और अन्य [(2013) 12 एससीसी ***480] #***, यह कहा गया है कि वह न्यायालय केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही राज्य जांच एजेंसी से किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जहां अदालत पक्षों के बीच न्याय करने और जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक

पाती है, या जहां राज्य पुलिस द्वारा जांच में विश्वसनीयता की कमी है और "निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच" होना आवश्यक है, और विशेष रूप से, जब राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है।

85. तथापि, आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने का प्रश्न ***रूबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य और अन्य*** ***(***2010) 2 एससीसी 200 ***में रिपोर्ट*** किए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ लाया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जा सकती है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ पैराग्राफ, 51, 52, 53, 54, 60 और 61 हैं जिन्हें यहां उद्धृत किया जा रहा है: -

> 51. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद और इस न्यायालय के समक्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई आठ कार्रवाई रिपोर्टों को देखने के बाद और बार में उद्धृत इस न्यायालय के निर्णयों और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद और राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने की मांग की गई अपराध की प्रकृति पर विचार करने के बाद, जो स्वयं इस तरह के अपराध में शामिल हैं, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इस स्तर पर जांच सीबीआई अधिकारियों या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को नहीं सौंपी जा सकती है। हम पहले ही गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी द्वारा उद्धृत निर्णयों पर चर्चा कर चुके हैं और पहले ही उक्त मामलों को अलग कर चुके हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वे निर्णय तब दिए गए थे जब

सीबीआई जांच पहले ही की जा चुकी है और उस स्तर पर इस न्यायालय ने कहा कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, सीबीआई प्राधिकारी इस न्यायालय से निदेश जारी करने के लिए इस न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर पाएंगे।

52. में *आर.एस. सोढ़ी* वी. *उत्तर प्रदेश राज्य* [1994 सप्प (1) एससीसी 143] जिस पर रिट याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किया गया था

, इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पीपी 144-45, पैरा 2)

> "*2*. ... हमने घटनाओं के बाद हुई घटनाओं का अवलोकन किया है, लेकिन हम इसके विवरण में प्रवेश करने से बच रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह किसी भी पक्ष को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर सकता है, लेकिन हमें लगता है कि *चूंकि आरोप स्थानीय पुलिस कर्मियों के खिलाफ निर्देशित हैं, इसलिए जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपना वांछनीय होगा ताकि मृतक के रिश्तेदारों सहित सभी संबंधित आश्वस्त महसूस कर सकें कि स्वतंत्र एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है और इससे जांच के अंतिम परिणाम की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। स्थानीय पुलिस चाहे जितनी निष्ठापूर्वक जांच करे, उसी पर विश्वसनीयता की कमी होगी क्योंकि आरोप उनके खिलाफ हैं*। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह सोचा कि जांच सीबीआई को सौंपना उचित और वांछनीय दोनों ही है और न्याय के हित में भी...'
>
> (महत्त्व सन्निविष्ट)

यह निर्णय स्पष्ट रूप से रिट याचिकाकर्ता को सीबीआई अधिकारियों या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने में मदद करता है।

53. वर्तमान मामले में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि आरोप स्थानीय पुलिस कर्मियों के खिलाफ निर्देशित किए गए हैं जिसमें गुजरात राज्य के उच्च पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता या यहां तक कि जनता के लिए यह कहना उचित होगा कि यदि गुजरात राज्य के पुलिस कर्मियों द्वारा की गई जांच की जाती है, तो रिट याचिकाकर्ता और उनके परिवार के सदस्य अत्यधिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे और जांच भी उचित निष्कर्ष के साथ समाप्त नहीं होगी और यदि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच करने की अनुमति दी जाती है, हमें लगता है कि मृतक के रिश्तेदारों सहित सभी संबंधित महसूस कर सकते हैं कि जांच उचित नहीं थी और उस परिस्थिति में यह उचित होगा कि रिट

याचिकाकर्ता और मृतक के रिश्तेदारों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि एक स्वतंत्र एजेंसी को इस मामले को देखना चाहिए और यह जांच के अंतिम परिणाम को विश्वसनीयता प्रदान करेगा, हालांकि स्थानीय पुलिस ईमानदारी से जांच कर सकती है, खासकर जब गुजरात राज्य के उच्च पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सकल आरोप लगाए गए हैं और जिसके लिए कुछ उच्च पुलिस अधिकारियों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है।

54. यह भी सर्वविदित है कि जब राज्य के पुलिस अधिकारी अपराध में शामिल थे और वास्तव में वे मामले की जांच कर रहे हैं, तो यह उचित होगा और न्याय के हित में बेहतर होगा यदि जांच सीबीआई अधिकारियों द्वारा की जाने का निर्देश दिया जाए, उस मामले में सीबीआई प्राधिकारी मामले की जांच करने के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी होंगे।

60.इसलिए, ऊपर की गई हमारी चर्चाओं के मद्देनजर, गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रोहतगी के तर्कों को स्वीकार करना मुश्किल है कि आपराधिक कार्यवाही में अदालत

में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद यह इस न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय के लिए भी खुला नहीं था कि वह मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश दे। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक उपयुक्त मामले में जब अदालत को लगता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच उचित दिशा में नहीं है और मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए और उच्च पुलिस अधिकारी उक्त अपराध में शामिल हैं, इसलिए अदालत के लिए हमेशा यह खुला था कि वह सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपे। यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, अदालत को उचित मामले में, सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार नहीं है।

61. इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् किसी उपयुक्त मामले में, न्यायालय को आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद भी अन्वेषण अन्वेषण ब्यूरो जैसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार प्राप्त है, अब हम इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं कि क्या ऐसी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अंतरित की जानी चाहिए

(ख) आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बावजूद सरकार ने प्राधिकारियों अथवा किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की है। इस आधार पर, हमने राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की गई आठ कार्रवाई रिपोर्टों और पेश की गई विभिन्न सामग्रियों और दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की प्रस्तुतियों की सावधानीपूर्वक जांच की है।

86. पूर्वोक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच से संतुष्ट न होने पर आरोप पत्र का अध्ययन करने के बाद मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जाने के लिए उपयुक्त समळाा है और तदनुसार,

जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी गई थी।

87. दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग दो तरीकों से कर सकता है, अर्थात, (i) राज्य की सहमति से यदि राज्य के भीतर शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना है; या (ii) संवैधानिक न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के आधार पर।

88. धारा 5 और धारा 6 में निर्दिष्ट शब्द "शक्ति और क्षेत्राधिकार" वर्तमान मामले में मुद्दे के निर्णय के उद्देश्य से प्रासंगिक है। "शक्ति और क्षेत्राधिकार" का अर्थ है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पारित किया जाता है, तो इस संबंध में सुश्री मायावती बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता ***है***

(2012) 8 एससीसी 106 ***में रिपोर्ट किया*** गया है जिसमें पैरा 29 में यह आयोजित किया गया है जो इसके तहत पढ़ता है: -

> "**29.** इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सेवा में प्रस्तुत किये संविधान पीठ द्वारा निर्णित निर्णय पश्चिम बंगाल *राज्य* बनाम *लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति* (2010) 3 एससीसी 571। राज्य और संघ से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 पर विचार करने के बाद, बेंच ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है: (एससीसी पी। 602, पैरा 69- 71)
>
> "*69*. अंतिम विश्लेषण में, संदर्भित प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक निर्देश
>
> संविधान की धारा 226 के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी राज्य की सहमति के बिना उसके राज्यक्षेत्र के भीतर कथित रूप से किए गए संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए न तो संविधान के संघीय ढांचे का अतिक्रमण होगा और न ही शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा और वह कानून में वैध होगा। नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक होने के नाते, इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न केवल शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी है, जो सामान्य रूप से भाग III द्वारा और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उत्साहपूर्वक और सतर्कता से गारंटीकृत है।

89.इसी प्रकार, निर्मल सिंह कहलों बनाम पंजाब राज्य और अन्य ***मामले में।***

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यह मानते हुए भी कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के कहने पर संदर्भ दिया गया था, वह

अपने आप में उसके द्वारा की गई जांच को पूर्णत अवैध और क्षेत्राधिकार के बिना नहीं बनाएगा क्योंकि यह मानते हुए कि संदर्भ उच्च न्यायालय द्वारा

जनहित याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, वह भी मान्य होगा, उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को इसके तहत संदर्भित किया जा रहा है: -

> 66. यह अधिनियम एक विशेष संविधि है। उक्त अधिनियमन के कारण, सीबीआई का गठन किया गया था। उन मामलों के संबंध में जो इसके दायरे में आने वाले थे, सीबीआई अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती थी। तथापि, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को क्षेत्राधिकार तभी प्राप्त होता है जब संविधि द्वारा इसके लिए सहमति दी जाती है। हालांकि, अब यह किसी भी विवाद से परे है कि उच्च न्यायालय और यह न्यायालय सीबीआई द्वारा जांच का निर्देश भी देता है। हमारा ध्यान सीबीआई मैनुअल के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया है, जिसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशक, सीबीआई मैनुअल के अध्याय VI में उल्लिखित मामलों के संबंध में अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करता है जिसमें राज्य द्वारा संदर्भ और/या उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय द्वारा संदर्भ के साथ-साथ उसका पंजीकरण भी शामिल है। उसका संदर्भ निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है:
>
> "(*a*) भारत के प्रधानमंत्री
>
> (आ) भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री/राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री या उनके समकक्ष
>
> (इ) राज्य सरकारें
>
> (ई) सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट।

सीबीआई नियमावली भारत संघ द्वारा तैयार किए जाने के बाद, स्पष्ट रूप से इसने स्वीकार किया है कि सीबीआई को जांच के लिए संदर्भ इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा भेजा जा सकता है। इस प्रकार, यह मानते हुए भी कि उच्च न्यायालय के कहने पर राज्य सरकार द्वारा संदर्भ दिया गया था, वही अपने आप में इसके द्वारा की गई जांच को पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं बनाएगा क्योंकि यह मानते हुए कि संदर्भ उच्च न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग में किया गया था

जनहित याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, यह भी मान्य होगा।

90. यह इस कारण से प्रासंगिक है कि उपर्युक्त तथ्य के आधार पर जिसे दोहराया नहीं जा रहा है क्योंकि इसका उल्लेख ऊपर किया गया है, कि इसमें शामिल मुद्दा अवैध खनन प्रचालन से संबंधित है और यद्यपि संबंधित जिले के उपायुक्त अर्थात् साहिबगंज जिले और जिला खनन अधिकारी को शिकायत की गई थी लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कोई निषेधात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी साथ ही रिट याचिका को वापस लेने में पक्षकारों का आचरण भी ताकि मामला सीबीआई को न सौंपा जा सके, जो शिकायतकर्ता द्वारा दायर किया गया था, क्योंकि शिकायत के बावजूद जिसे जीआर मामले के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन शिकायतकर्ता की रक्षा करने या अवैध खनन संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

91. समन्वय पीठ ने इसी बहाने रिट याचिका पर विचार किया है और पक्षकारों को बुलाया है। लेकिन जब यह लंबित था, आई ए संख्या 7438/2023 होने का एक अंतरवर्ती आवेदन उस अधिवक्ता द्वारा दायर नहीं किया गया था जिसने आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 होने के नाते रिट याचिका दायर

की थी, बल्कि वकालतनामा के आधार पर वकील का एक और सेट जेल प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था क्योंकि प्रासंगिक समय के दौरान उक्त शिकायतकर्ता एक अन्य मामले के संबंध में जेल में था।

92. पहले के वकील जिन्होंने की आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 होने के कारण रिट याचिका दायर की थी, ने भी वकालतनामा दायर किया था, जिसे जेल प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था।

93. ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान समन्वय पीठ ने उक्त अंतरवर्ती आवेदन पर विचार किया है, जिसे आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 के रिट याचिकाकर्ता के निर्देश पर दायर किया गया था, लेकिन वकील के परिवर्तन में आचरण को ध्यान में रखते हुए इसे खारिज कर दिया और बाद में, धुर्वा पुलिस स्टेशन, रांची में उस घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की, जहां उक्त शिकायत के शिकायतकर्ता पर रिट याचिका वापस लेने का जोर दिया जा रहा था।

94. इसलिए, समन्वय विद्वान समन्वय पीठ ने इस पर विचार किया है कि रिट याचिका को वापस लेने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय साजिश रची गई है, जिसके कारण विद्वान एकल न्यायाधीश ने योग्यता के आधार पर आदेश पारित करने के लिए अगली तारीख पर मामला तय करके उक्त अंतरवर्ती आवेदन को खारिज कर दिया।

95. समन्वयक विद्वान समन्वय पीठ ने शिकायत में निहित आरोप के संबंध में प्रारंभिक जांच करने के लिए आदेश पारित किया है।

96. यह सच है कि उक्त आदेश को झारखंड राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। हालांकि, पंकज मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने अपील आपराधिक (सीआरएल) संख्या 12087/2023 के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी है, जिसमें यह दलील दी गई है कि उसे आदेश पारित करने से पहले एक पक्ष बनाया जाना चाहिए था।

लेकिन उक्त याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। स्थगन आदेश देने के लिए किए गए अंतरिम अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया है। समन्वयित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता और औचित्य के संबंध में मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

97. यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि जब तक समन्वय विद्वान समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश संचालन में है और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने के अंतरिम स्थगन से इनकार करने के कारण संचालन में कहा जाएगा, जैसा कि दिनांक 04.12.2023 के आदेश से प्रकट होगा, और इस मामले के मद्देनजर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच करते समय, संज्ञेय अपराध करने की सामग्री पाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील (सीआरएल) संख्या 12087/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 को उद्धृत और संदर्भित किया जा रहा है: -

> 1. एसएलपी याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान, उत्तरदाता नंबर 3-सीबीआई के लिए पेश होने वाले विद्वान वकील श्री ज़ोहेब हुसैन, उत्तरदाता संख्या 1 के लिए श्री प्रद्युम्न गोहिल और उत्तरदाता संख्या 2-राज्य के लिए श्री चौधरी को विशेष अनुमति याचिका लंबित रहने तक आक्षेपित निर्णय पर रोक लगाने की मांग करने वाली अंतरिम राहत पर सुना।
>
> 2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उत्तरदाता नंबर 1, जो आपराधिक रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 665/2022 में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता था,

रिट याचिका के पैरा '20' में निहित निम्नलिखित राहत मांगी।

> "ए) उत्तरदाता, विशेष रूप से उत्तरदाता संख्या 1 के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश (ओं) या निर्देश (ओं) को जारी करने के लिए एसटी/एससी पीएस केस संख्या 06/22 दिनांक 1 दिसंबर 2022 को धारा 379, 323, 500, 504, 506, 120बी और 34, भारतीय दंड संहिता, 1860,शस्त्र अधिनियम की धारा 27 जेएमएमसी नियम, 2044 की धारा 04 और 54 के तहत पंजीकृत मामले की जांच सौंपने के लिए।
>
> और वर्तमान में अपर सत्र न्यायाधीश-I, साहिबगंज की अदालत में लंबित हैं। और
>
> आ) उचित रिट (ओं) को जारी करने के लिए, परमादेश की प्रकृति में आदेश (निर्देशों) को प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
>
> और/या
>
> इ) इस तरह के अन्य रिट (ओं), आदेश (ओं), या निर्देश (ओं) को जारी करने के लिए, जैसा कि यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता को विवेकपूर्ण न्याय करने वाले मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित सोच सकता है।

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त रिट याचिका को उत्तरदाता संख्या 1 (रिट-याचिकाकर्ता) द्वारा आईए नंबर 7438/2023 के रूप में एक अन्तरवर्ती आवेदन दायर करके वापस लेने की मांग की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.08.2023 के आदेश के माध्यम से अनुमति नहीं दी थी, जिसे आदेश दिनांक 18.08.2023 में पुन: प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद उच्च न्यायालय

ने गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर आगे कार्यवाही की और आक्षेपित आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में निम्नानुसार आयोजित किया:

> "29. इस मामले में, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसे इस न्यायालय ने ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर अस्वीकार कर दिया है। अवैध खनन के बारे में मामला याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज करने की कोशिश की गई थी जो पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया था, उसने विद्वान अदालत के समक्ष शिकायत मामला दायर किया और विद्वान अदालत ने दिनांक 07.07.2022 के आदेश द्वारा धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, हालांकि, उक्त प्राथमिकी 01.12.2022 को दर्ज की गई थी। प्रतिवादी राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में

अवैध खनन की जांच के संबंध में और पूरे जवाबी हलफनामे में, यह खुलासा किया गया है कि तकनीकी प्रकोष्ठ को मोबाइल नंबर के बारे में जांच करने का निर्देश दिया गया था और यह पाया गया था कि याचिकाकर्ता के मोबाइल का स्थान बंगलुरु का था जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने उक्त मोबाइल के बारे में पाया है जो किसी बिनोद प्रसाद का है जो बंगलुरू का निवासी है कि पुलिस अवैध खनन के पीछे मुख्य व्यक्तियों को बचा रही है। आगे का प्रश्न यह है कि यदि ऐसी बात संवैधानिक न्यायालय के संज्ञान में लाई जाती है, तो न्यायालय इसे पहुच से बाहर रहने दे सकता है या नहीं! इसका उत्तर केवल "नहीं" है क्योंकि बड़े पैमाने पर जनता यहां निष्पक्ष और निष्पक्ष पूछताछ/जांच की उम्मीद करती है। पैराग्राफ सं (ix) आईए संख्या 7438/2023 के अनुसार, यह कहा गया है कि 16.08.2023 को जब याचिकाकर्ता वकालतनामा पर अधिवक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, तो उस पर एक और वकील नियुक्त करने के लिए उसे फोन पर बुलाया गया था, जहां अशोक यादव और मुकेश यादव दोनों सकरी गली के निवासी हैं, जिरवाबारी, साहिबगंज सहित दो अन्य व्यक्तियों ने उसे घेर लिया और उसे जेल भेजने और मारपीट करने सहित कई तरह से धमकी दी।

30 उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, ऊपर चर्चा की गई, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह पर्याप्त रूप से पूरा होगा यदि निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस बात का अधिकार दिया जाएगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। इस याचिकाकर्ता सहित

आरोपी व्यक्तियों के आचरण की प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि उन्होंने एनओसी प्राप्त करने के माध्यम से एक नए वकील द्वारा दायर वकालतनामा पर रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है और इसके मद्देनजर, रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से जांच के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना भी उचित होगी। ऐसी प्रारंभिक जांच कानून के अनुसार की जाएगी और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो जाएगी।

31. याचिकाकर्ता को साहिबगंज पुलिस द्वारा संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि उसकी जान को खतरा है।

32. यह न्यायालय आशा और विश्वास करता है कि प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्य से नियुक्त अधिकारियों को व्यक्तिगत एजेंसियों से उचित विचार प्राप्त होगा, जिनसे संपर्क किया जाता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित सी.बी.आई. एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने और इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद, निदेशक, सीबीआई कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि निदेशक, सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है, तो वह इस आशय का उचित आदेश पारित कर सकता है।

33. उपरोक्त तथ्यों और कारणों और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त शर्तों में 2022 की डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 665 की अनुमति दी जाती है और इसका निपटान किया जाता है।

34. श्री श्याम दीवान, याचिकाकर्ता के लिए पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील, इस न्यायालय को 18.08.2023 के आक्षेपित आदेश में ले गए, मुख्य रूप से तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ टिप्पणियां की थीं और निष्कर्ष दर्ज किए थे, जो रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे, और सीबीआई को आरोपी व्यक्तियों के आचरण की प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया। "पंजाब राज्य बनाम दविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य: (2011) 14 एससीसी 770" के मामले में फैसले पर भारी भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच की मांग की गई है, उसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक है और उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया

जाना चाहिए।

35. श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील ने "डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य और अन्य: (2008) 3 एससीसी 542" के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है, साथ ही "प्रमोद कुमार बनाम भारत संघ और अन्य: (2018) 17 एससीसी 687" के मामले में भी, अपने सबमिशन को पुष्ट करने के लिए कि हालांकि संवैधानिक न्यायालय सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दे सकता है, अभियुक्त के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाले न्यायालय को उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

36. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को प्रारंभिक जांच का निर्देश नहीं देना चाहिए था, विशेष रूप से, जब रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ संदेह उठाया गया था कि क्या उसने स्वयं प्रार्थना के अनुसार निर्देश मांगने के लिए रिट याचिका दायर की थी।

37. प्रतिवादी-सीबीआई की ओर से पेश विद्वान वकील श्री ज़ोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार, सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की थी, और वर्तमान याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ RC024202350011 वाला मामला दर्ज किया था और इसलिए, वर्तमान याचिका निरर्थक हो गई है। उन्होंने "ई. शिवकुमार बनाम भारत संघ और अन्य: (2018) 7 एससीसी 365" के मामले में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया, यह प्रस्तुत करने के लिए कि निष्पक्ष जांच की मांग के लिए दायर एक रिट याचिका में, अभियुक्त जिसे पहले से ही प्राथमिकी में नामित किया गया है, को उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

38. श्री अरुणाभ चौधरी, प्रतिवादी-राज्य के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई है, हालांकि, यह आक्षेपित आदेश में देखा गया था कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जांच उचित हो सकती है।

39. पक्षकारों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील/वकील को विस्तार से सुनने के बाद, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता जो विचाराधीन प्राथमिकी के आरोपियों में से एक है, को न तो पक्षकार बनाने की

आवश्यकता थी, न ही प्रतिवादी नंबर 1 (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई की आवश्यकता थी। श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील का यह कहना कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, "ई. शिवकुमार बनाम भारत संघ और अन्य" (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसमें

"पंजाब राज्य बनाम दविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य" (सुप्रा) के मामले में, न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है:

> "10. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए दूसरे आधार का संबंध है, हम पाते हैं कि इस पहलू पर भी आक्षेपित निर्णय में विधिवत विचार किया गया है। आक्षेपित निर्णय के पैरा 129 में, दीनूभाई बोघाभाई सोलंकी बनाम गुजरात राज्य [दीनूभाई बोघाभाई सोलंकी बनाम गुजरात राज्य, (2014) 4 एससीसी 626: (2014) 2 एससीसी (सीआरआई) 384] पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली एक रिट याचिका में, अभियुक्त के मामले के रूप में सुनवाई के अवसर का हकदार नहीं था।गमन। रिलायंस को नरेंद्र जी गोयल बनाम भारत संघ में भी रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य [नरेंद्र जी. गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एससीसी 65: (2009) 2 एससीसी

(सीआरआई) 933], में

विशेष रूप से, रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैरा 11 जिसमें न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि अभियुक्त को जांच के चरण में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। जांच सीबीआई को सौंपकर, जो कि उपरोक्त के अनुसार, वर्तमान मामले के अजीबोगरीब तथ्यों के लिए अनिवार्य था, इस तथ्य का कोई फायदा नहीं होगा कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में या उस मामले के लिए नहीं सुना गया था, हमारी राय में, कोई फायदा नहीं होगा। यह स्वतः आक्षेपित निर्णय को शून्यता के रूप में लेबल करने का आधार नहीं हो सकता है।

11. हमारा ध्यान पंजाब राज्य [पंजाब राज्य बनाम दविंदर पाल सिंह भुल्लर, (2011) 14 एससीसी 770: (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 1034: (2012) 4 एससीसी (सीआरआई) 496: (2014) 1 एससीसी (एल एंड एस) 208] में की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया था, जो बदले में प्रदर्शनी के लिए विज्ञापन देता है डी. वेंकटसुब्रमण्यम वी. एम. के. मोहन कृष्णमाचारी [डी. वेंकटसुब्रमण्यम वी. एम.के. मोहन कृष्णमाचारी, (2009) 10 एससीसी 488: (2010) 1 एससीसी (सीआरआई) 358] , जिसमें यह माना गया है कि किसी पार्टी की पीठ के पीछे पारित एक आदेश एक शून्यता है और केवल इस स्कोर पर अलग रखा जा सकता है। ऐसा हो सकता है, यदि पार्टी की पीठ के पीछे पारित किए जाने

वाले आदेश को उस पार्टी के लिए कुछ नागरिक परिणाम देना था। लेकिन एक व्यक्ति जिसे आरोपी के रूप में नामित किया गया है

प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे अन्यथा जांच के चरण में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है या निश्चित रूप से सुनवाई का अवसर नहीं है, को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने के लिए जारी किया गया निर्देश एक अमान्य है। यह आधार, हमारी राय में, हताशा का तर्क है और खारिज किए जाने योग्य है।

40. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित स्पष्ट कानून के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं और इसे खारिज कर दिया गया है।

41. इस मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें।

42. इस बीच, पक्षकारों द्वारा दलीलें पूरी की जाएं।

43. अदालत द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर, पक्षकारों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह पूछताछ करने के लिए समय मांगा कि क्या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कोई प्रारंभिक जांच की गई है, हालांकि निर्देश नहीं दिया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में देखा गया है।

<u>डायरी नं. 35024/2023 और एसएलपी (सीआरएल) संख्या (एस)। 15345/2023</u>

छह सप्ताह के बाद इन मामलों की सूची बनाएं।

98 झारखण्ड राज्य ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी है जिससे यह पता चलता है कि झारखण्ड राज्य उक्त आदेश से व्यथित नहीं था बल्कि इसका

कारण झारखंड राज्य को ही अच्छी तरह ज्ञात था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर करके जांच को चुनौती देने के लिए उन्होंने यह रिट याचिका दायर क्यों की।

99 राज्य एक न्यायिक व्यक्ति है और यदि प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित समन्वय विद्वान समन्वय पीठ द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे को उठाया गया है,

विशेषकर, अवैध खनन कार्य के संबंध में, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि राज्य व्यथित है।

100 झारखंड राज्य की ओर से तर्क दिया गया है कि पुलिस ने पहले ही अनुसंधान शुरू कर दी थी।

101 सवाल यह है कि पुलिस द्वारा की जाने वाली उपरोक्त अनुसंधान उस समय भी उपलब्ध थी जब इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रारंभिक जांच करने का निर्देश पारित किया था।

102 इन सभी बातों पर विचार करने का कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 के प्रावधान के अनुसरण में कार्य करने के लिए आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में पारित दिनांक 18.08.2023 के आदेश द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम यानी सीबीआई को पहले ही शक्ति और अधिकार क्षेत्र निहित कर दिया गया है,.

103. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 5 और धारा 6 को पढ़ने से यह स्पष्ट होगा कि दो भागों अर्थात् जांच के संबंध में शक्तियों और क्षेत्राधिकार या अनुसंधान के संबंध में शक्ति और क्षेत्राधिकार का कोई पृथक्करण नहीं है, बल्कि शब्द राज्य की सहमति से शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार है, चाहे वह प्रारंभिक जांच हो या नियमित सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दर्ज की गई अनुसंधान

नियमित मामला। जिस क्षण इस न्यायालय ने प्रारंभिक जांच अनुसंधान एजेंसी को सौंपने का आदेश पारित किया है, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के दायरे में आता है और ***ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य*** के मामले में (***2014) 2 एससीसी 1***, और पैरा

सीबीआई अपराध मैनुअल के 9.1 में प्रावधान है कि यदि प्रारंभिक जांच के दौरान कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है, तो नियमित मामला स्थापित किया जाना है, इसलिए, एक बार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसी को इस न्यायालय द्वारा शक्ति और अधिकार क्षेत्र का विस्तार प्रदान किए जाने के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1946 के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आगे निदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है और यही कारण है कि समन्वय न्यायपीठ ने उपर्युक्त आदेश में निदेशक, सीबीआई को कानून के अनुसार कार्य करने का निदेश दिया है।

104. यहां यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि अध्याय 9 के तहत सीबीआई अपराध मैनुअल में प्रारंभिक जांच

करने की प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध है।

9.1 में कहा गया है कि *"प्रारंभिक जांच को नियमित मामले में परिवर्तित किया जा सकता है जैसे ही यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किया गया है"।*

> 105. इसलिए, जब सीबीआई अपराध मैनुअल में यह प्रावधान है कि यदि प्रारंभिक जांच करने के दौरान कोई संज्ञेय अपराध पाया गया है, तो

इसे नियमित मामले में परिवर्तित किया जाना है जो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य ***(सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अभिप्राय है***, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त होने पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस के कर्तव्य को रेखांकित किया था जब संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करता है। पूर्वोक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को यहां उद्धृत किया जा रहा है: -

> **"120.3।** यदि जांच में संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है, तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने में समाप्त होती है, इस तरह के बंद होने की प्रविष्टि की एक प्रति पहले परिवादी को तुरंत और एक सप्ताह के बाद नहीं दी जानी चाहिए। इसे शिकायत को बंद करने और आगे नहीं बढ़ने के कारणों का संक्षेप में खुलासा करना चाहिए।
>
> **120.4.** संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है। प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ

कार्रवाई की जानी चाहिए, अगर उनके द्वारा प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

106. प्रारंभिक जांच करने के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय ***जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य बनाम थौमंडरू हन्ना विजयलक्ष्मी @ टीएच विजयलक्ष्मी और अन्य के मामले में*** 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 923 ***में रिपोर्ट किया गया है,*** जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सभी मामलों में प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है।

जहां मामला अनुपातहीन संपत्ति के कब्जे से जुड़ा हो

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 24 में पूर्वोक्त निर्णय में अवधारित किया है जो इस प्रकार है:-

> **"24.** मानागीपेट [तेलंगाना राज्य बनाम *मानागीपेट,]* में दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय (2019) 19 एससीसी 87: (2020) 3 एससीसी (सीआरआई) 702] ने इसके बाद नोट किया है कि *जबकि ललिता कुमारी* [*ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, (2014) 2 एससीसी 1: (2014) 1 एससीसी (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय (सीआरआई) 524] ने निर्णय दिया कि अभिकथित भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है जो अभियुक्त को प्रारंभिक जांच की मांग करने का अधिकार नहीं देता है। प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और इसे अनिवार्य आवश्यकता नहीं कहा जा

सकता है जिसके बिना भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। हेमंत गुप्ता, जे. इस प्रकार आयोजित किया गया: (*मनागीपेट मामला* [*तेलंगाना राज्य* v. *मानागीपेट*, (2019) 19 एससीसी 87, पैरा 33-34: (2020) 3 एससीसी (सीआरआई) 702]

, एससीसी पीपी 103-105, पैरा 28-30 और 32-34)

"*28. ललिता कुमारी में* [*ललिता कुमारी* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य*, (2014) 2 एससीसी 1: (2014) 1 एससीसी (सीआरआई) 524] में*न्यायालय ने निर्धारित किया है* कि वे मामले *जिनमें किसी अभियुक्त के पक्ष में कोई अधिकार निहित करने के बजाय कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता* है। इसमें, तर्क दिया गया था कि यदि एक पुलिस अधिकारी को किसी आरोप की सत्यता के बारे में संदेह है, तो उसे प्रारंभिक जांच करनी होगी और कुछ उपयुक्त मामलों में, ऐसे अधिकारी के लिए यह उचित होगा कि संज्ञेय अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, वह खुद को संतुष्ट करे कि प्रथम दृष्टया, शिकायत में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप विश्वसनीय हैं। ...

29. न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है यदि सूचना से संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है। ...

30. *यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने यह नहीं माना है कि सभी मामलों में प्रारंभिक जांच जरूरी है*। वैवाहिक विवादों/पारिवारिक विवादों, वाणिज्यिक अपराधों, चिकित्सा लापरवाही के मामलों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि के संबंध में प्रारंभिक जांच की जा सकती है। *ललिता कुमारी* [*ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, (2014) 2

एससीसी 1: (2014) 1 एससीसी (सीआरआई) 524]के निर्णय में *यह नहीं कहा गया है कि प्रारंभिक जांच किए बिना किसी अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है*।

***

32.... प्राथमिकी *दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का दायरा और दायरा आवश्यक होना प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। प्रारंभिक जांच करने का कोई निर्धारित प्रारूप या तरीका नहीं है। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि एक तुच्छ और असमर्थनीय शिकायत पर आपराधिक जांच प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है। ललिता कुमारी* [*ललिता कुमारी बनाम* उत्तर *प्रदेश राज्य*, (2014) 2 एससीसी 1: (2014) 1 एससीसी (सीआरआई) 524] में यही जांचने का तरीका निर्धारित किया गया है

33. वर्तमान मामले में, प्राथमिकी से ही पता चलता है कि एकत्र की गई जानकारी आरोपी अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति के संबंध में है। प्रारंभिक जांच का उद्देश्य निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए पूरी तरह से तुच्छ और प्रेरित शिकायतों की जांच करना है। इसमें, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले प्रथम दृष्टया आरोपों के संबंध में परिवादी के पास प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध थी। इसलिए, एक बार प्राथमिकी दर्ज करने वाला अधिकारी इस तरह के खुलासे से संतुष्ट हो जाता है, तो वह बिना किसी जांच के या किसी अन्य तरीके से उसके द्वारा प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ सकता है। *यह नहीं कहा जा सकता है कि* प्राथमिकी *को इस कारण से रद्द किया जा सकता है कि प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी। ऐसा तभी किया जा सकता है जब* प्राथमिकी *की संपूर्णता को पढ़ने पर किसी अपराध का खुलासा न हो*। इस संबंध में संदर्भ, इस न्यायालय के एक निर्णय के लिए किया गया है हरियाणा राज्य

। बनाम*भजन लाल* [*हरियाणा राज्य* बनाम *भजन लाल*, 1992 सप्प (1)

एससीसी 335: 1992 एससीसी (सीआरआई) 426] जिसमें, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं और जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण रूप से की जाती है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से एक गुप्त रूप से शुरू की जाती है अभियुक्त से प्रतिशोध लेने का उद्देश्य और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे अपमानित करने के उद्देश्य से।

34. *इसलिए, हम मानते हैं कि ललिता कुमारी* [*ललिता कुमारी बनामउत्तर प्रदेश राज्य*, (2014) 2 एससीसी 1: (2014) 1 एससीसी (सीआरआई) 524] *में अवश्यक प्रारंभिक जाँच भ्रष्टाचार के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से संचालित होने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय द्वारा कई उदाहरणों में यह दोहराया गया है कि प्रारंभिक जांच का प्रकार प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ऐसे कोई निश्चित मापदंड नहीं हैं जिनके आधार पर ऐसी जांच की गई हो। इसलिए,* प्राथमिकी *दर्ज करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के लिए संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी का कोई भी औपचारिक और अनौपचारिक संग्रह पर्याप्त है*।

(महत्त्व सन्निविष्ट)"

107. पूर्वोक्त पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जहां प्रथम *दृष्टया* संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले आरोप के बारे में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध है,

प्राथमिकी दर्ज करने वाला अधिकारी प्रारंभिक जांच किए बिना सूचना के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ सकता है।

108. पैराग्राफ 37 और 39 के तहत पूर्वोक्त निर्णय में यह माना गया है जो इसके तहत पढ़ता है: -

"**37.** यदि प्रारंभिक जांच आवश्यक है तो इसे सीबीआई मैनुअल के अध्याय 9 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पैरा 9.1 नोट:

"**9.1।***जब कोई शिकायत प्राप्त होती है या ऐसी सूचना उपलब्ध होती है जो इस मैनुअल में दिए गए सत्यापन के बाद, लोक सेवक की ओर से गंभीर कदाचार का संकेत दे सकती है, लेकिन धारा 154 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत नियमित मामले के पंजीकरण को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रारंभिक जांच दर्ज की जा सकती है*... जब किसी शिकायत और स्रोत की जानकारी के सत्यापन से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है, तो कानून द्वारा आदेशित एक नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पीई को आरसी में परिवर्तित किया जा सकता है जैसे ही यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किया गया है। *जब उपलब्ध जानकारी संज्ञेय अपराध के कमीशन को इंगित करने के लिए पर्याप्त है या इसके विवेकपूर्ण सत्यापन से समान निष्कर्ष निकलता है, तो प्रारंभिक जांच के बजाय एक नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए, यह आवश्यक है कि एसपी को सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट का*

मूल्यांकन करते समय उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए ताकि पीड़ के पंजीकरण का सहारा न लिया जाए जहां एक नियमित मामला दर्ज किया जा सकता है।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

अतः उपर्युक्त से दो विशिष्ट सिद्धांत उभरकर सामने आते हैं: (*i*) एक प्रारंभिक जांच तब दर्ज की जाती है जब

सत्यापन के बाद सूचना (शिकायत या "स्रोत सूचना" से प्राप्त) एक लोक सेवक की ओर से गंभीर कदाचार को इंगित करती है लेकिन नियमित मामले के पंजीकरण को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है; और (ii) जब उपलब्ध जानकारी *या* इसके गुप्त सत्यापन के बाद एक संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता है, तो प्रारंभिक जांच का सहारा लेने के बजाय एक नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए अनिवार्य रूप से।

39. इस न्यायालय के उदाहरण और सीबीआई मैनुअल के प्रावधान यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है

उन सभी मामलों में जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। *ललिता कुमारी* [*ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, (2014) 2 एससीसी 1: (2014) 1 एससीसी (सीआरआई) 524] धारण करता है

कि यदि प्राप्त सूचना से प्रारंभ में ही संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है, तो किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। इसने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त सूचना की सत्यता की जांच करना नहीं है, बल्कि केवल यह जांचना है कि क्या यह एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करता है।

इसी तरह, सीबीआई मैनुअल के पैरा 9.1 में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता केवल तभी होती है जब सूचना (चाहे सत्यापित या असत्यापित) एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करती है। यहां तक कि जब प्रारंभिक जांच शुरू की जाती है, तो जैसे ही अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है जो संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है, इसे रोकना होगा। इसी तरह का निष्कर्ष *मानागीपेट* [*तेलंगाना राज्य बनाम*]मानागीपेट में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निकाला गया है।, (2019) 19 एससीसी 87:

(2020) 3 एससीसी (सीआरआई) 702] भी। इसलिए, यह प्रस्ताव कि प्रारंभिक जांच अनिवार्य है, कानून के स्पष्ट रूप से विपरीत है, क्योंकि यह *ललिता कुमारी* [*ललिता कुमारी* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य*, (2014) 2 एससीसी 1: (2014) 1 एससीसी (सीआरआई) 524] में संबिधानिक खण्डपीठ के फैसला के बिपरीत ही नहीं बल्कि

सीबीआई मैनुअल द्वारा बनाए गए ढांचे को भी फाड़ देगा।

109. उपरोक्त फैसले के पैराग्राफ 37 से यह स्पष्ट है कि (*i*) प्रारंभिक जांच तब दर्ज की जाती है जब सत्यापन के बाद सूचना (शिकायत या "स्रोत सूचना" से प्राप्त) एक लोक सेवक की ओर से गंभीर कदाचार का संकेत देती है लेकिन नियमित मामले के पंजीकरण को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है; और (*ii*) जब उपलब्ध जानकारी *या* इसके गुप्त सत्यापन के बाद

संज्ञेय अपराध के मामले में, प्रारंभिक जांच आवश्यक रूप से करने के बजाय एक नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

110. इसके अलावा, पैराग्राफ 39 में यह माना गया है कि ***ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य*** (सुप्रा) में संविधान पीठ के निर्णय में कहा गया है कि यदि प्राप्त जानकारी से संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा होता है, तो शुरुआत में एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा होता है, कोई प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। इसने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त सूचना की सत्यता की जांच करना नहीं है, बल्कि केवल यह जांचना है कि क्या यह एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करता है।

111. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त पैराग्राफ में सीबीआई मैनुअल के पैरा 91 को नोट किया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रारंभिक जांच केवल तभी अपेक्षित है जब सूचना (चाहे सत्यापित हो या असत्यापित) किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा न करती हो। यहां तक कि जब प्रारंभिक जांच शुरू की जाती है, तो जैसे ही अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है जो संज्ञेय अपराध के कमीशन का

खुलासा करती है, इसे रोकना होगा।

112. इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रस्ताव रखा है कि प्रारंभिक जांच अनिवार्य है, कानून के स्पष्ट रूप से विपरीत है, क्योंकि यह ललिता ***कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य*** (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ के निर्णय के न केवल विपरीत है

लेकिन सीबीआई मैनुअल द्वारा बनाए गए ढांचे को भी फाड़ देगा।

113. उपरोक्त मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल ***कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड अदर्स बनाम भारत संघ और अन्य*** ***(***2022) 4 एससीसी 764 ***में रिपोर्ट*** किए गए मामले में भी विचार किया गया है, जिसमें प्रारंभिक जांच और सीबीआई अपराध मैनुअल के मुद्दे पर ध्यान दिया गया है, जिसका अर्थ है, चूंकि सीबीआई अपराध नियमावली के पैरा 91 में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होते ही कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है। प्रारंभिक जांच को नियमित मामले में परिवतत किया जाए

114. पैरा 9.1 के अनुसार सीबीआई मैनुअल के आधार पर कानून पहले ही तय किया जा चुका है, जिसमें

प्रारंभिक जांच के दौरान किसी भी संज्ञेय अपराध की सतह के मामले में, ***ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य*** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर उसे नियमित प्राथमिकी में परिवर्तित किया जाना है।

115. पैरा 9.1 के तहत सीबीआई अपराध मैनुअल भी प्रारंभिक जांच को नियमित मामले में बदलने के संबंध में बोलता है यदि प्रारंभिक जांच करने के दौरान संज्ञेय अपराध पाया गया है।

116. अब जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है कि एक बार उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है और यदि संज्ञेय अपराध सामने आया है, तो क्या उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक नए निर्णय की आवश्यकता हो सकती है या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत प्रदान की गई सहमति की आवश्यकता हो सकती है, की आवश्यकता है और दिनांक 18.08.2023 के आदेश में शब्द का अर्थ क्या होगा *"एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने और उस प्रभाव की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद,* ***निदेशक,***

सीबीआई कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे"/ यहाँ, "कानून के अनुसार" ***का अर्थ क्या है***।

117. "कानून के अनुसार" शब्द का असर हो रहा है और यदि न्यायालय ने प्रारंभिक जांच का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया है और यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने आती है, तो निदेशक, सीबीआई को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।

118. इसलिए, आज की स्थिति के अनुसार कानून में केवल संज्ञेय अपराध के कमीशन से संबंधित सामग्री की आवश्यकता है

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (सुप्रा) ***के मामले में दिए गए संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार***, ऐसी परिस्थितियों में प्राथमिकी दर्ज की जानी है ।

119. समन्वय विद्वान समन्वय पीठ ने सीआरपीसी की धारा 482, यानी आपराधिक विवध याचिका संख्या 3378/2023 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2023 में संशोधन के लिए निर्देश मांगा गया है।

120. समन्वय विद्वान समन्वय पीठ ने दिनांक

18.08.2023 के आदेश में पारित पहले के निर्देश को ध्यान में रखते हुए उक्त याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें निदेशक को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश पहले से ही है।

121. उपर्युक्त आदेश को झारखंड राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए, उक्त आदेश, जहां तक याचिकाकर्ता की क्षमता में झारखंड राज्य का संबंध है, लंबित विशेष अनुमति याचिका के परिणाम के अधीन बाध्यकारी है, जिसमें उसी आदेश को चुनौती दी गई है, हालांकि झारखंड राज्य द्वारा नहीं बल्कि एक निजी पार्टी द्वारा, अर्थात्, पंकज मिश्रा। उक्त विशेष अपील की अनुमति (आपराधिक) के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसी आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है कि झारखंड राज्य भी अपील की विशेष अनुमति (आपराधिक) का पक्षकार है।

122. अनुसंधान पर रोक लगाने के लिए भी अनुरोध किया गया है, इसलिए समन्वय पीठ ने सीबीआई द्वारा अनुसंधान पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया।

123. लेकिन, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच में अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो

झारखंड राज्य इस न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को कैसे उठा सकता है। झारखंड राज्य का उक्त आचरण अनुचित प्रतीत होता है, वह भी ऐसे मामले में जहां मुद्दा अवैध खनन प्रचालन के विरुद्ध था जिसका निहितार्थ देश भर में है क्योंकि यह मामला अवैध तरीकों से खनन अयस्कों के उत्खनन से संबंधित है।

124. अतः झारखण्ड राज्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कर्त्तव्यबद्ध है। तथापि, झारखण्ड राज्य ने अवैध खनन के मुद्दे से निपटने के लिए झारखंड खनन खनिज रियायत नियम और गौण खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 नामक एक नियम भी बनाया है।

125. एक व्यक्ति को खुद का बचाव करने के आदेश में रुचि रखने के लिए कहा जा सकता है कि वह अवैध खनन कार्य में शामिल नहीं है, लेकिन राज्य द्वारा जांच पर सवाल उठाने का कारण कहां है यदि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जांच करने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि यहां मामले का तथ्य है।

126. समन्वय पीठ साहिबगंज जिले के जेल अधीक्षक द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित दो वकालतनामा जारी करने के संचालन का भी ध्यान रखा है।

यहां, झारखंड राज्य में प्रक्रिया यह है कि यदि एक वकालतनामा पहले ही दायर किया जा चुका है, तो जेल अधीक्षक द्वारा उसकी मुहर देने के बाद विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है, संबंधित जेल में रखे जाने के लिए रिकॉर्ड में उचित प्रविष्टियां की जानी हैं, तो किन परिस्थितियों में उस वकील से अनापत्ति के मुद्दे की पुष्टि किए बिना नया वकालतनामा दिया गया है जिसके द्वारा रिट याचिका अनुसंधान सीबीआई को सौंपने के लिए दायर की गई है।

127. इस न्यायालय को इस मुद्दे पर नहीं जाना है क्योंकि यह न्यायालय समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश पर अपील में नहीं बैठा है।

128. लेकिन, यह न्यायालय, फिलहाल, याचिकाकर्ता राज्य झारखंड की ओर से उठाए गए मुद्दे पर विचार कर रहा है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नए निर्देश या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत आवश्यक राज्य की सहमति के संबंध में है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2022 की में दिनांक 18.08.2023 को पारित आदेश आज के रूप में क्षेत्र में है और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश पहले से ही है, तो हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, "***कानून के अनुसार***" शब्द का अर्थ सीबीआई अपराध नियमावली के अनुसार पैराग्राफ के अनुसार

है

9.1 जहां प्राथमिकी शुरू करके प्रारंभिक जांच को नियमित मामले में बदलने का प्रावधान है और संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए

और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य ***(सुप्रा)*** के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए

129. यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 2022 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 665 में दिनांक 18.08.2023 के आदेश के अनुसार एक नियमित मामला स्थापित करने का कोई निर्देश नहीं है, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरण के जवाब में तर्क दिया गया है।

130. लेकिन, इस न्यायालय को इस तरह के तर्क में कोई बल नहीं मिलता है क्योंकि जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि समन्वयक विद्वान एकल न्यायाधीश ने निदेशक को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया है और जब कानून प्राथमिकी शुरू करके प्रारंभिक जांच को नियमित मामले में बदलने का है, तो यदि इस तरह का प्रतिबिंब

नियमित मामले को दर्ज करने के आदेश में है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देश को गलत नहीं कहा जा सकता है।

131. जहां तक याचिकाकर्ता राज्य झारखंड राज्य के विद्वान वकील की ओर से दुर्भावना का मामला बनाने के लिए उद्वेलित तथ्यात्मक पहलू का संबंध है, लेकिन जब इस न्यायालय ने कानूनी आधार के आधार पर इस मुद्दे पर विचार किया है, चाहे वह दुर्भावना से हो या सदाशयता, वह अभी भी गर्भ में है और वह जांच के समापन के बाद आएगा जब अंतिम प्रपत्र होगा प्रस्तुत।

132. इसके अलावा, चूंकि इस न्यायालय ने उस परिदृश्य में एक मुद्दे से निपटा है जहां पहले से ही एक निर्देश पारित किया गया है

सीबीआई अपराध नियमावली के पैरा 9.1 के अनुसार, संज्ञेय अपराध सामने आने के बाद, इस न्यायालय के लिए यह न्यायसंगत और उचित नहीं होगा कि वह दुर्भावना के उक्त मुद्दे पर निर्णय ले क्योंकि यह न्यायालय नए सिरे से शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है कि क्या प्रारंभिक जांच या जांच सौंपी जानी है सीबीआई को , बल्कि, रिट याचिका का मुद्दा यह है कि केवल इसलिए कि प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया है, इसे नियमित मामला दर्ज करके जांच के लिए आगे बढ़ने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

133. यह न्यायालय, यहां ऊपर दिए गए तर्क के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा

है कि प्रारंभिक जांच को नियमित मामले में बदलना है

सीबीआई अपराध नियमावली के 9.1 के अनुसार, जैसा कि नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड अदर्स बनाम भारत संघ और अन्य ***(सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है***, इसलिए भी दुर्भावना के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि यह तथ्यात्मक पहलुओं पर निर्भर करता है।

> 134 .यदि दुर्भावना के मुद्दे पर समन्वयक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ध्यान दिया गया है और यदि उस पर विचार किया जाएगा, तो यह समीक्षा करने के समान होगा

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2023 के आदेश में की गई टिप्पणियां/निष्कर्ष।

135. इसके अलावा, यह न्यायालय आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में दिनांक 18.08.2023 के आदेश पर अपील में नहीं बैठा है।

136. तदनुसार, दोनों मुद्दों का उत्तर दिया गया है।

137. पूर्वोक्त कारण के आधार पर इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका में योग्यता का अभाव है।

138. आदेश देने से पहले, श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्कों में से एक, कि दुर्लभतम मामले में जांच सीबीआई को सौंपी जानी है, इस संबंध में डिवाइन ***रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य और अन्य*** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है।

139. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दुर्लभतम या दुर्लभ मामलों में पूरी सावधानी बरतते हुए आदेश पारित करते

हुए अनुसंधान सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए.

140. यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि यह न्यायालय मामले को नए सिरे से सीबीआई को सौंपने के मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा है, बल्कि, आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में दिनांक 18.08.2023 के आदेश में समन्वय पीठ द्वारा पहले से ही निर्देश पारित किया गया है और एकमात्र मुद्दा है कि अगर प्रारंभिक अनुसंधान करने का निर्देश दिया गया है, तो उच्च न्यायालय द्वारा नए निर्देश या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत राज्य की सहमति की आवश्यकता है या नहीं।

141. इस न्यायालय ने पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय ले लिया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के दायरे में आने

वाली जांच एजेंसी को प्रारंभिक जांच सौंपने के समन्वय पीठ द्वारा पहले से पारित आदेश के मद्देनजर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आगे निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है।

142. इसके अतिरिक्त, चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पहले से ही निदेश मौजूद है और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***पश्चिम बंगाल और अन्य*** (सुप्रा) *बनाम* ***लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति,*** के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में दिये गए निर्णय के अनुसार उच्च नयायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुसंधान सौंपने की शक्ति है

इसके अनुसरण में विद्वान समन्वय पीठ ने 18.08.2023 को आपराधिक रिट याचिका संख्या 665/2022 में आदेश पारित किया है।

143. इसके अतिरिक्त, प्रारम्भिक जांच के दौरान यदि संज्ञेय अपराध सामने आता

है तो नियमित मामला दर्ज किया जाना होता है, इसलिए आज जो कानून विद्यमान है वह यह है कि एक बार प्रारम्भिक जांच का निदेश मिल जाने के बाद नियमित मामला संस्थित किया जाना चाहिए और जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

144. इसलिए, वर्तमान में, पूर्वोक्त निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है।

145. तदनुसार, तत्काल रिट याचिका खारिज की जाती है।

146. दिनांक 19.01.2024 का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे।)

बीरेंद्र **/ए.एफ.आर.**

[यह अनुवाद शिववचन यादव , पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया]